

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>
वनवासियों में जगा सरकार के प्रति...



साय कैबिनेट बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अधीन होगा। डामर के दाम बढ़ने के कारण अनुबंधित ठेकेदारों को क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले

मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रेप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी एवं व्यवस्थित निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है तथा 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था। रूझष्ट के अत्याधुनिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रेप सामग्री खरीद सकते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और राज्य को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।

इस व्यवस्था से राज्य में स्क्रेप निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, तकनीक आधारित

जीएडी के अधीन होगा कर्मचारी चयन मंडल, सड़क ठेकेदारों को भी राहत

और राजस्वोन्मुख हुई है। इस निर्णय से विभागों को अलग-अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा।

मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है किछत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का विलय नए कर्मचारी चयन मण्डल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां भी नए मण्डल में शामिल हो गई हैं।

राज्य मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में 01 अप्रैल 2026 के पश्चात बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण और अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य के हित और निर्माण कार्यों

में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

यह राहत केवल बिटुमिन मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए निर्धारित फार्मुले के आधार पर दी जाएगी। अन्य निर्माण घटकों पर

अनुबंध में पूर्व से प्रावधानित एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे। वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण डामरीकरण कार्य प्रभावित होने लगे थे, जिससे सड़क निर्माण और संधारण कार्यों की गति बाधित होने की आशंका थी। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए इसी प्रकार की राहत के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हों और विकास कार्यों की गति बनी रहे, जिससे जनता को निर्धारित समय पर सड़क निर्माण कार्यों का

लाभ मिल सके।

कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किया जाएगा। सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम-2026 लागू होने के बाद पूर्व के व्यापम का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां भी नए मंडल को ट्रांसफर कर दी गई हैं।

ठेकेदारों को राहत

मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को सीमित और आंशिक राहत देने का फैसला लिया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। सरकार ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बढ़ने से सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे थे। ऐसे में निर्माण कार्यों की गति बनाए रखने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंचा ‘कॉकरोच’ अभियान

नई दिल्ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बने ‘कॉकरोच’ शब्द को अब इंडियन यूथ कांग्रेस ने राजनीतिक अभियान का रूप दे दिया है। संगठन ने युवाओं से जुड़े मुद्दों—जैसे पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार—को लेकर ‘इंडियन यूथ कॉकरोच’ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। युवा कांग्रेस का दावा है कि उसके कार्यकर्ता केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए जेल, मुकदमे तथा प्रशासनिक कार्रवाई तक झेल चुके हैं।युवा कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह अभियान संगठन के प्रभारी मनीष शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब के नेतृत्व में शुरू किया गया है। संगठन



ने इसे युवाओं के सामूहिक प्रतिरोध की आवाज बताया है। उदयभानु चिब ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल डिजिटल बहस तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता असली कॉकरोच की तरह हर कठिन

परिस्थिति में युवाओं के मुद्दों के लिए मैदान में डटे रहे हैं। उनके मुताबिक, पेपर लीक विरोध प्रदर्शन, छात्र आंदोलन और रोजगार से जुड़े अभियानों में कार्यकर्ताओं ने लगातार संघर्ष किया है।युवा कांग्रेस का कहना है कि संगठन मुकदमों, जेल, धमकियों और बैंक खातों पर रोक जैसी कार्रवाइयों से डरने वाला नहीं है। हाल में आयोजित एआई समिट के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए संगठन ने दावा किया।

प्रमुख समाचार

केरल के मुख्यमंत्री सतीशन ने पीएम मोदी से की मुलाकात

नईदिल्ली। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात की, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की सत्ता में वापसी के बाद एक महत्वपूर्ण क्षण था। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए कई



महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और वित्तीय पैकेजों हेतु केंद्र से समर्थन मांगने के लिए एक विस्तृत जापन प्रस्तुत किया, साथ ही केरल से संबंधित कई लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की। हालाँकि चर्चाओं का आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन यह ज्ञात है कि बुनियादी ढांचा विकास, वित्तीय सहायता, लंबित रेलवे और राजमार्ग परियोजनाएं, आपदा राहत सहायता और केरल की समग्र वित्तीय स्थिति से संबंधित मुद्दे वार्ता में प्रमुखता से शामिल थे। सतीशान बैठक स्थल से निकलते समय चुप रहे और प्रधानमंत्री के साथ हुई चर्चाओं के परिणाम के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देने से बचते रहे।

पीएम मोदी से आज मिलेंगे तमिलनाडु सीएम विजय

चेन्नई। सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पदभार संभालने के बाद बुधवार को पहली बार नई दिल्ली की यात्रा पर जा रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, विजय बुधवार सुबह चेन्नई से रवाना होंगे और गृह सचिव समेत राज्य के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय राजधानी यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि विजय के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने की व्यवस्था की गई है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात करने की संभावना है। दिल्ली दौरे के दौरान, विजय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे। यह दौरा विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के कुछ सप्ताह बाद हो रहा है।

एआईएडीएमके के चौथे विधायक ने भी दिया इस्तीफा

चेन्नई। तमिलनाडु में इन दिनों सियासी हलचल देखने को मिल रही है। एआईएडीएमके के चौथे विधायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एआईएडीएमके विधायक एसाक्की सुबाया ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया, जिससे वह दो दिनों में ऐसा करने वाले पार्टी के चौथे विधायक बन गए हैं। सुबया उन बागी विधायकों में से हैं, जो पूर्व राज्य मंत्रियों सी. वे. शनमुगम और एसपी. वेलुमणि का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने 13 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान टीवीके सरकार का कहना है कि संगठन मुकदमों, जेल, धमकियों और बैंक खातों पर रोक जैसी कार्रवाइयों से डरने वाला नहीं है। हाल में आयोजित एआई समिट के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए संगठन ने दावा किया।

विधान परिषद् की नौ सीटों पर चुनाव की घोषणा

पटना। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद की नौ सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली की गई सीट भी शामिल है। चुनाव आयोग ने पूर्व बिहार



मुख्यमंत्री नौतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद खाली की गई विधान परिषद सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, सभी नौ सीटों के लिए मतदान, उपचुनाव सहित, 18 जून को होगा और मतगणना उसी शाम की होगी। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 20 जून तक समाप्त होने की उम्मीद है। चुनाव अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है।

बीजद छोड़ भाजपा सदस्य बने ओडिशा के पूर्व सांसद देबाशीष

नई दिल्ली। ओडिशा के पूर्व राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बीजू जनता दल (बीजद) छोड़कर भाजपा के साथ नई राजनीतिक पारी शुरू करने का फैसला लेने वाले देबाशीष पर बीजद ने स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया है। बीजद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के बाद देबाशीष सामंतराय ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके कार्यक्रमों और व्यक्तित्व से प्रेरित होकर

मैं आज भाजपा में शामिल हो रहा हूं। ओडिशा में भाजपा के लिए मुझे बहुत काम करना है; मैं पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मंगलवार को भाजपा प्रवक्ता सह उत्तराखंड से निर्वाचित लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि 11 बजे दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रख्यात हस्ती को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। उनके इस एक्स पोस्ट के बाद भाजपा में नई सियासी हस्ती के आगमन को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई थी।

सेवा, सुरक्षा और सुशासन के बेमिसाल 12 साल

सुरेश पवौरी

लोकतीव्र में श्रेष्ठ नेतृत्वा की पहचान नीति, नीयत और निष्ठाल की कसौटी पर खरा उतरने से होती है। यह एक सुखद पक्ष है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस मापदंड पर सर्वथा खरे उतरे हैं। देश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की प्रथम बार शपथ ली। बतौर प्रधानमंत्री अपने 12 वर्ष के लगातार कार्यकाल में उन्होंने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में स्वीकारा तथा देशवासियों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे।

नरेन्द्र मोदी ऐसे कर्मयोगी हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिन् के राष्ट्र-भाव को चरितार्थ करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वादस का संकल्प लेकर भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने में अहर्निश लगे हुए हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्रम सरकार का सिद्धांत है- रीफार्म, परफार्म एवं ट्रांसफार्म। प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प

की सिद्धि के लिए अपनी प्राथमिकता में तड्डह को रखा है। त् का तात्पर्य गरीब, ङ्ग का तात्पर्य युवा, का तात्पर्य अन्नदाता किसान और ह का तात्पर्य नारी। वर्तमान में केंद्र सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं में इन पर अधिक फोकस किया है।

गरीब कल्याणि कार्यक्रम

केन्द्रा सरकार ने समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित एवं सर्वहारा वर्ग के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक ऐतिहासिक एवं कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छद भारत अभियान की शुरुआत की। पिछले 12 वर्षों में यह अभियान एक जन आंदोलन बन गया है। साथ ही उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत करोड़ो लोग लाभान्वित हुये हैं।



किसान कल्याण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन बहुत साफ़ है कि किसानों को उनकी पैदावार का सही दाम मिले। इस बाबत् फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में रिकार्ड बढ़ोतरी की। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को उनके बैंक खातों में हर चार महीनों में दो हजार रुपये पहुंचाये जाते हैं। पीएम फसल बीमा योजना

युवा शक्ति की बेहतरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में युवाओं के लिए अच्छाल स्वामस्स्थ , फिटनेस और उन्हे उचित हुनर से लैस करना शामिल है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा कोष योजना और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत को विकसित राष्टी की ओर आगे बढ़ाया है।

एवं राष्टीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवाई) से अन्ननदाता लाभान्वित हो रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के विकास एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। मातृवंदन योजना, नारी शक्ति वंदन और 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगी है। केन्द्रा सरकार का लक्ष्यस तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लखपति दीदी अपना गरिमामय जीवन जी रही हैं। बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों का आत्मषसम्पाकन बढ़ा है। तीन तलाक कानून की समाप्ति से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है।

स्वाषस्कर सुविधाओं में वृद्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्वर वाली केन्द्रा सरकार ने देश में लगभग 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं। मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि

समाज के हर वर्ग खासकर सामान्य लोगों तक सतीन , सुलभ एवं गुणवत्ता 2पूर्ण स्वासस्थति सेवाएं पहुंचें। इस दिशा में जारी प्रयास के परिणाम स्वरूप अस्पसताल,इलाज और दवाओं पर होने वाला खर्च निरन्तईर कम होता जा रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने स्तुदेशी वैक्सिलन के आविष्कार में प्रेरक भूमिका निभाई।

सांस्कृ तिक विरासत का संरक्षण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना संकल्प् विरासत का, संरक्षण भी और विकास भी के परिणाम स्वरूप अयोध्यात में रामलला की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठो सम्पन्नअ हुई। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, बद्रीनाथ क्षेत्र का विकास, करतार साहब कॉरिडोर को खुलवाना, हेमकुण्डव साहब और गिरनार में रोपवे बनाना, नमामि गंगे योजना, तिरुवल्लू में कलत्सरर सेन्टसर बनाना आदि उल्लेखनीय कार्यों से भारत आत्मागौरव के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

‘अपनापन’ के विमोचन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय



मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक ‘अपनापन’ के विमोचन समारोह में शामिल हुए। यह पुस्तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ श्री चौहान के सार्वजनिक जीवन, आत्मीय संबंधों और कार्य अनुभवों पर आधारित है, जिसमें नेतृत्व, जनसेवा और व्यक्तिगत संवेदनाओं को प्रेरक एवं भावनात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री शिवराज सिंह चौहान को पुस्तक के प्रकाशन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से समाज तक पहुँचाना एक प्रेरणादायी पहल है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास जनप्रतिनिधियों के अनुभवों, कार्यशैली और जनसेवा के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनसेवा, सुशासन और संवेदनशील नेतृत्व की नई कार्यसंस्कृति विकसित हुई है। इस पृष्ठभूमि में सार्वजनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित यह पुस्तक निश्चित रूप से पाठकों को प्रेरित करेगी तथा नेतृत्व और समाजसेवा के विभिन्न आयामों को समझने का अवसर प्रदान करेगी। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्रीगण, देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि और अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वित्तमंत्री चौधरी ने दी शुभकामनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी



चौधरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर ऐतिहासिक 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि 26 मई 2014 से शुरू हुआ यह 12 वर्षों का कार्यकाल देश के इतिहास में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प का जीवंत प्रतीक रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अत्योदय के लक्ष्य को साकार किया है। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाया है। जनधन योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों, किसानों और माताओं-बहनों के जीवन को गरिमापूर्ण बनाया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं और देश में अभूतपूर्व पारदर्शिता सुनिश्चित की है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि यह कालखंड देश के नव-निर्माण और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाला रहा है। इन 12 वर्षों में भारत ने वैश्विक पटल पर विकास, सुशासन, डिजिटल परिवर्तन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से सीएम साय ने की मुलाकात

रायपुर। दो दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन से भेंट मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों और छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति देने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी साझा की है। सीएम साय के सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के दौरान प्रश्न में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने, गरीबों के कल्याण, किसानों के हित, युवाओं के रोजगार और मातृशक्ति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बता दें कि साल 2021 से 2024 के बीच नितिन छत्तीसगढ़ में सह-प्रभारी रहे। पार्टी ने उन्हें साल 2024 में छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव प्रभारी बने।

बकरीद अवकाश की तारीख में बदलाव अब 28 मई को रहेगी सार्वजनिक छुट्टी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तारीख में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पहले बकरीद के लिए 27 मई बुधवार को अवकाश घोषित किया गया था, जिसे बदलकर अब 28 मई गुरुवार कर दिया गया है। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक GENs-1001/86/2025-GAD-5 06 नवंबर 2025 में वर्ष 2026 के लिए घोषित सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाशों की सूची में बकरीद के लिए 27 मई का अवकाश निश्चित था। अब राज्य शासन ने आंशिक संशोधन करते हुए 28 मई 2026 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। इस निर्णय के बाद राज्य के सभी शासकीय कार्यालय, स्कूल-कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थान 28 मई को बंद रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण, मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने दी बधाई

मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को मिली नई गति : साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘प्रधान सेवक’ के रूप में राहसेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी, निर्णायक और जनकेंद्रित नेतृत्व में भारत ने सेवा, सुरक्षा, आत्मविश्वास और विकास के नए युग में प्रवेश किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शासन की सोच और कार्यशैली को बदलते हुए सेवा, सुशासन और अत्योदय की भावना को केंद्र में रखा तथा यह सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, महिला, युवा, वंचित और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री

नरेंद्र मोदी ने लिया, वह आज देश के कोने-कोने में दिखाई देता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत आत्मविश्वास, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक अधोसंरचना, डिजिटल क्रांति, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समावेशन की दिशा में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। विकसित भारत /2047 का संकल्प आज जनभागीदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व विशेष रूप से प्रेरणादायी रहा है। दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे बस्तर और वनांचल क्षेत्रों में आज विकास, विश्वास और जनकल्याण की नई धारा दिखाई दे रही है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधाओं



और शासकीय योजनाओं की पहुँच दूरस्थ जनजातीय अंचलों तक सुनिश्चित हुई है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, जन-धन योजना और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने गरीबों, किसानों, मातृशक्ति, युवाओं तथा जनजातीय समाज के जीवन में आशा, सम्मान और

आत्मविश्वास का नया संचार किया है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच ने शासन को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि

आधार बनाया। इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को केवल नारा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे व्यवहार और नीति का आधार बनाया। इसी का परिणाम है कि आज देश विकास और सामाजिक समावेशन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का नेतृत्व देश को केवल आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बना रहा, बल्कि सांस्कृतिक

आत्मगौरव, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी की भावना को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए देशवासियों में नए आत्मविश्वास का संचार किया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनकल्याण, सुशासन और अत्योदय के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को मिले।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समस्त छत्तीसगढ़वासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना की तथा विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

भाजपा विधायक पुरंदर हुए ठगी के शिकार

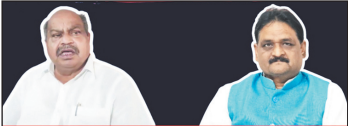
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

कहा- कानून व्यवस्था बंद से बदतर

रायपुर।

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा के साथ हुई ठगी मामले में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के दिन सही नहीं चल रहे हैं। राज्य में बीजेपी सरकार का खोफ खत्म हो गया है। नितिन नवीन के पीए के नाम पर ठगी की गई। प्रदेश में भाजपा राज में रसूखदारों से पैसे उगाही का खेल चल रहा है। कानून व्यवस्था बंद से बदतर हो गई है।

सुशील शुक्ला ने कहा कि बीते दिनों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के साथ लूट हुई थी, अब बीजेपी के विधायक के साथ ठगी हो गई। ठगी भी ऐसे विधायक के साथ हुई जो अधिवक्ता और इनकम टैक्स के सलाहकार हैं। राज्य में आरोपियों के हाँसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सवाल उठाने हुए कहा कि जब भाजपा के दो विधायकों के साथ ऐसा हो सकता है, तो सोचने वाली बात है कि आम आदमी के साथ क्या होगा। रामभद्राचार्य और



धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के दिए बयान से सियासत तेज है। मामले में विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि डॉ। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर कथावाचकों पर टिप्पणी कर रहें हैं। उनसे अपील है कांग्रेस के चक्कर में न पड़े। जिस तिगड़ी में फंसे हैं, उससे ऊपर उठ कर देशहित में बात करें।

विधायक पुरंदर मिश्रा के बयान पर पटलवार करते हुए कांग्रेस नेता सुशील शुक्ला ने कहा कि वह चरणदास महंत को सीख न दें। कांग्रेस के किसी भी नेता को बीजेपी नेताओं से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। डॉ. महंत ने रामभद्राचार्य पर टिप्पणी की, वह सही है। रामभद्राचार्य भाजपा के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं।

आगे कहा कि रामचरित मानस और हनुमान चालीसा की चौपाइयों में गलतियां निकालने वाला क्या बात करेगा।

चरणदास महंत को जगदगुरु रामभद्राचार्य की खुली चुनौती

■ कहा- दुर्भाग्यशाली नेता प्रतिपक्ष, नेतृत्व की शक्ति है तो मेरे जगदगुरुत्व का पूर्ण परीक्षण कर लें

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। भाजपा के प्रचारक हैं और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं, ऐसे लोगों को न मैं जगदगुरु मानता हूँ ना राम का गुरु मानता हूँ। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के इस बयान पर जगदगुरु रामभद्राचार्य ने कड़ी आपत्ति जताई है। जगदगुरु रामभद्राचार्य ने महंत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनमें नेतृत्व की शक्ति है तो मेरे जगदगुरुत्व का पूर्ण परीक्षण कर लें। चिरमिरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में चल रही श्रीराम कथा के नौवें दिन उस समय महाहौल गरमा गया, जब जगदगुरु रामभद्राचार्य ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर तीखा पलटवार किया। व्यासपीठ से संबोधित करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि उन्हें जगदगुरु नहीं मानने वालों को वे खुली चुनौती देते हैं कि उनका पूर्ण परीक्षण कर लिया जाए। रामभद्राचार्य ने ये भी बताया कि जगदगुरु कौन कहलाता है। उन्होंने बताया,



जगदगुरु बनने की पहली शर्त है जो ब्रह्मचारी और विरक्त होना चाहिए। दूसरी शर्त तीन ग्रंथों पर भाष्य लिखने वाला जगदगुरु होता है, जिसमें ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पर, इस तीनों को मैंने लिखा है, जो छपा भी है। 12 उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा है। नारद भक्त सूत्र और श्री रामस्तवराज स्योत और वेद स्तुति भागवत पर भी लिखा है। जिसका समर्थन काशी विदुपरिषद और सभी अखाड़े करते हैं, कुंभ में जिसका सबसे पहला स्नान होता है, वहीं जगदगुरु होता है।

जगदगुरु रामभद्राचार्य ने कहा मैं हर कसौटी पर खरा हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। रामभद्राचार्य ने कहा कि जो भी भगवान श्रीराम से प्रेम करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। कुछ लोगों को इससे

मिर्ची लग रही है, लेकिन सनातन और रामभक्ति को कोई रोक नहीं सकता, उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों का उल्लेख करते हुए कहा कि रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान वे महीनों जेल में रहे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, वो दिन आप भूल गए जब निहत्थे रामभक्तों पर लाठियां ही नहीं

बल्कि गोलायों तक चलवाई गई थीं। हमने रामजन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिए,

जगदगुरु रामभद्राचार्य ने देश के विभाजन और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही देश को गति में ले जाया गया, देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया।

रामभद्राचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का उल्लेख करते हुए कहा कि जोगी थोड़े अच्छे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं क्या बताऊँ। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष की इतनी असभ्यता कि संतों के बारे में कैसे बोला जाता है, इसका भी सामान्य ज्ञान नहीं है।

राज्यपाल डेका ने की पीएम जनमन योजना की समीक्षा

■ विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से पहुंचे

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज लोक भवन में प्रधानमंत्री जनजाति आवादीसा न्याय महाअभियान (पीएम जनमन योजना) की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने योजनाओं का लाभ उन तक प्राथमिकता से पहुंचाना सुनिश्चित करें।

बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता तय कर तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों की सड़कों की खराब स्थिति पर भी नाराजगी जताई और अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें और यह जाँचें कि पीएम जनमन योजना के तहत उनके विभाग अंतर्गत सबसे बेहतर कार्य कहाँ हो रहे हैं।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन अभियान चलाने तथा लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।



उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से जनजातीय समुदायों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाकर उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है।

राज्यपाल ने बताया कि जनजातीय बच्चों के नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए एम्स के साथ एमओयू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए राइस मिल एसोसिएशन, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने और डीएनएफ निधि के उपयोग का सुझाव दिया। साथ ही बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने और पेयजल समस्या के समाधान हेतु नवाचार अपनाने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने बड़े किसानों के खेतों में डबरी निर्माण, फिश फार्मिंग और प्रधानमंत्री आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे जल संरक्षण और वाटर रिचार्ज को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में वन क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग को सहकारिता के माध्यम से करने, आंगनबाड़ी भवन निर्माण में तेजी लाने तथा मोबाइल टावर स्थापित कर इंटरनेट सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने निजी कंपनियों के सहयोग से

बस किराया बढ़ाने की मांग

डीजल महंगा होने पर परिवहन मंत्री से मिले छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारी

रायपुर। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने बस किराया बढ़ाने की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारी परिवहन मंत्री केदार कश्यप से मिलने पहुंचे और अपनी मांगों से संबंधित जापन सौंपा।

यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सैयद अनवर अली ने कहा कि प्रदेश में आखिरी बार सितंबर 2021 में यात्री किराए में वृद्धि की गई थी। उसके बाद से बसों के संचालन खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बीते 15 दिनों में डीजल के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। इसके अलावा बसों के चैंचिस, बॉडी, टायर, बीमा, मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और कर्मचारियों के वेतन सहित सभी खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर व्हीकल फिटनेस, सीट बेल्ट, स्पीड गवर्नर, पैनिंक बटन, हार्ड सिस्कोरिटी नंबर प्लेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य किया गया है, जिससे बस संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है।

महासंघ ने कहा कि 11 मार्च 2025 की



अधिसूचना के बाद यात्री किराए में करीब 25 प्रतिशत तक कमी की गई थी, जबकि डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 90 प्रतिशत से अधिक बस संचालक आर्थिक रूप से प्रभावित हो चुके हैं। महासंघ ने मांग की है कि सामान्य यात्री बसों के किराए में 50 प्रतिशत और डीलान्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाए।

प्रश्न अध्यक्ष सैयद अनवर अली ने कहा कि रायपुर से जगदलपुर का वर्तमान किराया करीब 600 रुपए है, जो बढ़ोतरी के बाद 700 से 750 रुपए तक हो सकता है। वहीं रायपुर से दुर्ग का किराया 50 रुपए से बढ़कर करीब 75 रुपए तक पहुंच सकता है।

छत्तीसगढ़ में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का डीए बढ़ा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 58 फीसदी की जगह 60 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में

कहा गया है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। यह भुगतान जनवरी 2026 से नकद रूप में किया जाएगा।

मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना वेतन मेंट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन या अन्य अतिरिक्त भत्तों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही आदेश के विपरीत

अधिक भुगतान होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी से राशि की वसूली भी की जाएगी। हालांकि, दूसरी ओर राज्य संवर्ग के अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनर्स अब भी डीए बढ़ोतरी की मांग पर कायम हैं। लंबे समय से कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और केंद्र के समान दर लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए आदेश जारी होने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड, राजनांदगांव (छ.ग.)				
द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना				
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से मेन्सुअल निविदा "प्रपत्र-अ"में प्रतिशत दर पर एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से जिला खनिज संस्थान न्यास मद अंतर्गत राजनांदगांव जिले के विकासखंड डोंगरगांव में निम्नलिखित कार्यों हेतु मुरबन्द निविदाये दिनांक 22.05.2026 को आमंत्रित की जाती है। (सम्पूर्ण कार्य सामग्री सहित संलग्न शेड्यूल अनुसार)				
निविदा प्रपत्र क्रय करने के लिये खंड कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 11.06.2026 है। उपरोक्त निविदा की अन्य शर्तें, विस्तृत विवरण व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।				
क्र.	निविदा सूचना क्रमांक	विकासखण्ड	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1	22	डोंगरगांव	डोंगरगांव आवर्धन योजना अंतर्गत इटकवेल एवं डबल्यू.टी.पी. के मंटेनेंस कार्य	10.20
2	23	डोंगरगांव	ग्राम आर्री में पॉपिंग मेन, नल कनेक्शन एवं छिन्नीयेशन हाईप लाईन कार्य।	11.30
कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड राजनांदगांव (छ.ग.)				
जी-262700975/5				

राज्यसभा चुनाव : राजनीतिक दल खेला करने की तैयारी में!

नीरज कुमार दुबे

18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव और दो उपचुनाव देश की संसदीय राजनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखे जा रहे हैं। कुल 26 सीटों पर होने जा रहे इस चुनाव में सत्ता पक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दलों के बीच संतुलन में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सीमित राजनीतिक लाभ मिल सकता है। यह चुनाव केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि आने वाले समय में संसद के भीतर शक्ति मण्डल, विधायी रणनीति और क्षेत्रीय दलों की भूमिका को भी प्रभावित करेगा। हम आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि राज्यसभा की 24 सीटों के लिए नियमित चुनाव तथा महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक-एक सीट पर उपचुनाव 18 जून को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है। जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौडा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तथा केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू शामिल हैं। इन चुनावों में आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की चार-चार सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तीन-तीन सीटों, झारखंड की दो सीटों तथा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की एक-एक सीट पर मतदान होगा। मौजूदा स्थिति में इन 26 सीटों में से 18 सीटें एनडीए के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास चार, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास तीन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक सीट है। विधानसभाओं के मौजूदा संख्याबल को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि राज को एक सीट का नुकसान हो सकता है, जबकि कांग्रेस अपने खाते में एक या दो सीटों की बढ़ोतरी कर सकती है। भाजपा के 12 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन पार्टी लगभग 11 सीटें सुरक्षित रख सकती है। हालांकि झारखंड में यदि उसे कॉंस वोटिंग का लाभ मिलता है या आंध्र प्रदेश में सहयोगी तेलुगू देसम पार्टी का समर्थन मिलता है, तो वह संभावित नुकसान से बच सकती है। कर्नाटक इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है। वहां कांग्रेस तीन सीटें जीत सकती है, जबकि भाजपा को एक सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और पार्टी वहां अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने की कोशिश करेगी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को दो-दो सीटें तथा कांग्रेस को एक-एक सीट मिलने की संभावना है। गुजरात में भाजपा चारों सीटें जीत सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश में तेलुगू देसम पार्टी के सभी चार सीटें जीतने के आसार हैं। झारखंड में मुकाबला विशेष रूप से दिलचस्प है। वहां झामुमो और कांग्रेस गठबंधन के पास पर्याप्त विधायक संख्या है और दोनों सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस झामुमो से एक सीट की मांग कर रही है। यदि यह रणनीति सफल होती है तो कांग्रेस की राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच सकती है। भाजपा यहां विपक्षी खेमे में संंध लगाने और कॉंस वोटिंग के जरिये एक सीट नुकवाने की कोशिश कर सकती है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के उपचुनाव भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलनाा वेत्री कणगम के पहली बार राज्यसभा में पहुंचने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो यह दक्षिण भारत की राजनीति में एक नए क्षेत्रीय शक्ति केंद्र के उभरने का संकेत होगा। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या राजग समर्थित उम्मीदवार की जीत की संभावना है।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

अर्थात- इस वंश में केशव भगवान् के भक्त, राजा लोग प्रायः अमोघ वीर्य्य (=जिनका वीर्य्य किसीभी दशा में निष्फल न जाये तादृश) होते हैं। सो इस सद्योमृत र।जा के शरीरस्थ, अमोघ वीर्यं को ऋषियों ने वैज्ञानिक ढंग से मथन कर उससे सन्तान को प्राप्त किया। तात्पर्य यह है कि वर्तमान अनुसन्धायकों ने अनेक यन्त्रों के प्रयोग से इस बात का पता लगाया है कि वीर्य के प्रत्येक कग में अगणित कीटाणु होते हैं जो तदि्धा अणु-वीक्षण यन्त्र से देखे भी जा सकते हैं, परन्तु वे कीटाणु इतने मृदु लतीफ होते हैं कि प्राणी-शरीर से वीर्य्य के च्युत होते ही बाह्य वातावरण के प्रभाव से प्रायः तत्काल ही मर जाते है, यही दशा रजोगत कीटाणुवों की समझनी चाहिए।

गर्भाधान के समय रजोवीर्य के कीटाणु एक दूसरे को खाना आरम्भकर देते हैं और इस तरह आन की

आन में अन्त में केवल एक कीट शेष रह जाता है। यदि वीर्य के अधिक प्रबल होता है तो अन्त में वीर्या-ध्वज्य के कारण पुरुषत्व-प्रधान कीट वचता है जो दशवं महीने पुत्र सन्तान के रूप में परिणत होकर उत्पन्न होता है। इसी तरह रजः के प्राबल्य से कन्या की उत्पत्ति, और दोनों के समाग हो जाने पर नपुंसक का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। सो गर्भाशयादि के दुष्ट होने की दशा में उक्त कीटाणु उसके विषेले वातावरण में तत्काल मर त्राते हैं, अतएव गर्भस्थिति नहीं हुवा करती। यह तो हुई राधारण रजोवीर्य की बात! अब अमोघ वीर्य का भी रहस्य समझिये।

सृष्टि के आरम्भ काल में स्वभावतः और फिर आगे चलकर अमुक अमुक साधनों द्वारा नियमित आहार विहार पूर्वक जीवन बिताने सफल अचूक किंवा बाह्य वातावरण की दशा में पुरुष का वीर्य अमोघ की शीतोष्णता को भरसक सहन कर सकने की क्षमता वाला हो जाया करता है। **क्रमशः ...**



युद्ध के परिणाम किसी एक देश तक सीमित नहीं रहते

देवी एम. चेरियन

आज की दुनिया गहराई से जुड़ी हुई है। जब एक देश संघर्ष का रास्ता चुनता है, तो उसके परिणाम केवल उसकी अपनी सीमाओं के भीतर नहीं रहते। वे ईंधन की कीमतों, खाद्य लागत, शिपिंग मार्गों, नौकरियों और मुद्रास्फीति और महंगाई आदि के माध्यम से फैलते हैं। यही कारण है कि कई आम लोगों को लगता है कि जब शक्तिशाली देश युद्ध में जाते हैं तो वे केवल एक-दूसरे से नहीं लड़ रहे होते, वे बाकी दुनिया को उन फैसलों की कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहे होते हैं जो उनके कभी थे ही नहीं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। भले ही यह किसी दूर के संघर्ष का हिस्सा न हो लेकिन इसके नागरिक फिर भी दैनिक जीवन में इसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, रसोई गैस महंगी हो जाती है और परिवहन की लागत बढ़ जाती है। एक मध्यमवर्गीय परिवार जो अपने हर रूपए का प्रबंधन सावधानी से करता है, अचानक अपने मासिक बजट को दबाव में पाता है। युद्ध भले ही दूर कहीं हो रहा हो लेकिन उसकी कीमत उनकी रसोई की मेज तक पहुंच जाती है।

यही कारण है कि कई लोग ऐसे संघर्षों को बाकी दुनिया के साथ अन्यथा के रूप में देखते हैं। अक्सर युद्ध सत्ता के संघर्ष, क्षेत्रीय विवादों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं या नेताओं द्वारा समझौता करने से इंकार करने के कारण शुरू होते हैं। कुछ मामलों में व्यावहारिक समझदारी की तुलना में गर्व, प्रतिद्वंद्विता या राष्ट्रीय अहंकार अधिक मजबूत हो जाता है। जब देश यह विश्वास करते हुए कि वे ताकत के बल पर परिणाम बदल सकते हैं, इस तरह के राजनीतिक अहंकार में आकर काम करते हैं तो बोज़ केवल उन तक ही सीमित नहीं रहता। यह उन देशों और लोगों तक फैल जाता है जिनकी इस विवाद में कोई आवाज नहीं थी।

रूस और यूक्रेन ने दिखाया है कि कैसे एक क्षेत्रीय युद्ध दुनिया भर में असर डाल सकता है। ऊर्जा



की कीमतें बढ़ गईं, अनाज का निर्यात बाधित हो गया और एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के देशों में महंगाई बढ़ गई। जिन देशों का मूल संघर्ष से कोई लेना-देना नहीं था, उन्हें भी ईंधन और भोजन के लिए अधिक भुगतान करना पड़ा। यही वैश्विक अन्याय है। आर्थिक नुकसान सांझा हो जाता है, भले ही राजनीतिक निर्णय केवल कुछ ही लोगों द्वारा लिया गया हो।

यही स्थिति तब भी होती है जब तेल उत्पादक क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है। प्रमुख शिपिंग लेन के पास संघर्ष तुरंत तेल की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। चूंकि भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए इसका सीधा असर पड़ता है। डीजल की कीमतें ट्रकिंग, खेती और सार्वजनिक परिवहन को प्रभावित करती हैं। इसका मतलब यह है कि दूध से लेकर दवा तक सब कुछ महंगा हो जाता है। मध्यम वर्ग इसे हर दिन महसूस करता है तथा गरीब इसे और भी अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। मध्यम वर्ग के लिए यह संघर्ष अक्सर शांत होता है क्योंकि वे इतने गरीब नहीं हैं कि कई सहायता योजनाओं के पात्र बन सकें लेकिन इतने अमीर भी नहीं हैं कि बढ़ती लागतों को नजरअंजान कर सकें। उनकी सैलरी वेंसी ही रह सकती है जबकि हर बिल बढ़ जाता है। किराया, स्कूल की फीस, किराना, बिजली और स्वास्थ्य सेवा सब बढ़ जाते हैं। वही पारिवारिक आय हर महीने कम सामान खरीद पाती है। यहीं पर किसी एक खर्च के कारण नहीं

ज्ञान/मीमांसा

लोकतांत्रिक चुनौती के बीच जनगणना

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत वर्ष 2027 में अपनी पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना कराने जा रहा है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत की शासन व्यवस्था, विकास नीति और लोकतांत्रिक ढांचे में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का संकेत है। जिस प्रकार स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ने नवगठित राष्ट्र को अपनी जनसंख्या, संसाधनों और सामाजिक संरचना को समझने का आधार दिया था, उसी प्रकार 2027 की डिजिटल जनगणना भारत को डेटा-आधारित शासन के नए युग में प्रवेश कराने वाली है। यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है, जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन, सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल, क्लाउड-आधारित रियल-टाइम डेटा अपलोड, जियो-टैगिंग और डिजिटल डैशबोर्ड जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद कोविड-19 महामारी सहित कई कारणों से 2021 की जनगणना टलती चली गई। परिणामस्वरूप देश को लगभग 14 वर्षों तक पुराने आंकड़ों पर निर्भर रहना पड़ा। इस दौरान भारत में शहरीकरण, प्रवासन, रोजगार संरचना, डिजिटल उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या वितरण में भारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसे में 2027 की जनगणना केवल एक सांख्यिकीय अभ्यास नहीं होगी, बल्कि यह आधुनिक भारत की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने का माध्यम बनेगी। विशेष बात यह है कि यह पहली बार होगा जब भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में इतनी बड़ी जनगणना डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी।

डिजिटल जनगणना का सबसे बड़ा लाभ इसकी गति और दक्षता में दिखाई देता है। पारंपरिक कागजी जनगणना में डेटा एकत्र करने, उसकी जांच करने, कोडिंग, प्रविष्टि और विश्लेषण में दो वर्ष या उससे अधिक समय लग जाता था। लेकिन डिजिटल प्रणाली में डेटा सीधे सर्वर पर अपलोड होगा, जहां स्वचालित सत्यापन और विश्लेषण की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे प्रारंभिक परिणाम दस दिनों के भीतर और अंतिम विस्तृत रिपोर्ट छह से नौ महीनों में उपलब्ध हो सकती है। यह बदलाव केवल समय बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण की गति और सटीकता को भी कई गुना बढ़ा सकता है। यदि



सरकार के पास समय पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होंगे, तो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, आवास और शहरी नियोजन जैसी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

डिजिटल प्रणाली में त्रुटियों को कम करने की भी व्यापक संभावना है। मोबाइल एप्लिकेशन में प्री-कोडेड विकल्प, ऑटो-फिल, रियल-टाइम वैलिडेशन और जियो-कोडिंग जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे गलत प्रविष्टियों की संभावना कम होगी। प्रत्येक भवन को एक विशिष्ट भौगोलिक निर्देशांक से जोड़ा जाएगा, जिससे न केवल भवनों की सही गणना संभव होगी बल्कि विकास योजनाओं के लिए स्थान-आधारित विश्लेषण भी आसान होगा। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र में स्कूलों, अस्पतालों या जलस्रोतों की उपलब्धता का विश्लेषण जनसंख्या घनत्व के साथ जोड़ा जा सकेगा। इससे सरकार को यह समझने में आसानी होगी कि किन क्षेत्रों में संसाधनों की कमी है और कहाँ निवेश की आवश्यकता अधिक है।

डिजिटल जनगणना का एक और महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता है। नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी भर सकेंगे और उसे सत्यापित कर सकेंगे। इससे सरकारी आंकड़ों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ सकता है। डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर प्रगति की निगरानी भी संभव होगी। यह प्रणाली प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत कर सकती है और डेटा संग्रह की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बना सकती है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो भारत दुनिया के लिए डिजिटल प्रशासन का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि, इन संभावनाओं के साथ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती भारत का डिजिटल विभाजन है। आज भी देश के करोड़ों लोग इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक समान पहुंच नहीं रखते। ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और उत्तर-पूर्व के कई

प्रियंका कौशल

डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म तत्कालीन मध्यप्रदेश (वर्तमान छत्तीसगढ़) में एक छोटी सी रियासत खैरागढ़ में 27 मई 1894 को हुआ था। उस वक खैरागढ़ राजनांदागंज जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ का एक जिला है। खैरागढ़ वही स्थान है, जहां एशिया का पहला संगीत व कला विश्वविद्यालय स्थापित है। लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना के कहीं पहले ही बख्शी जी के कारण खैरागढ़ विश्वपटल पर चर्चित रहा है। उनके पिता का नाम पुन्नालाल बख्शी व माता का नाम मनोरमा देवी था। इनके घर का वातावरण साहित्यिक था, यही कारण था कि बाल्यकाल से ही इनके मन मस्तिष्क पर लिखने पढ़ने का असर रहा। इनके पिता

खैरागढ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गुरु के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल का सानिध्य भी इनको मिला।

बख्शी जी ने अध्यापन से लेकर संपादन तक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, आलोचना, यात्रा संस्मरण सभी विधाओं पर लिखा है। किंतु उनके निबंधों ने उन्हें विशेष ख्याति दिलाई है। पर ये भी सत्य है कि उनके साहित्य के अनुरागी इनकी हर विधा के प्रशंसक रहे हैं। यही कारण है कि बख्शी जी का साहित्य आज भी उतना ही लोकप्रिय है। उनका पहला निबंध सरस्वती में सोना निकालने वाली चंटीयां नाम से प्रकाशित हुआ था। बीए पास करने के बाद उन्होंने राजनांदगांव में 1916 से संस्कृत शिक्षक के रूप में सेवाएं

हिस्सों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर या अनुपलब्ध है। यदि जनगणना का अत्यधिक निर्भरता डिजिटल माध्यमों पर रही, तो समाज के सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्ग जनगणना से बाहर छूट सकते हैं।

भारत में डिजिटल साक्षरता भी एक बड़ी चुनौती है। बुजुर्ग, अशिक्षित लोग, ग्रामीण महिलाएं और प्रवासी मजदूर अक्सर स्मार्टफोन एप्लिकेशन या ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग करने में सहज नहीं होते। यदि केवल तकनीक के भरोसे डेटा संग्रह किया गया, तो गलत जानकारी, अधूरी प्रविष्टियां और अंडरकाउंटिंग की संभावना बढ़ जाएगी। अफ्रीकी देशों में डिजिटल जनगणना के कुछ प्रयोगों में यह देखा गया था कि कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में त्रुटियों की दर काफी अधिक रही। भारत में यह चुनौती और भी जटिल हो सकती है क्योंकि यहां भाषाई, सामाजिक और आर्थिक विविधता अत्यंत व्यापक है। इसलिए केवल डिजिटल होना पर्याप्त नहीं होगा; यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक समावेशी और उपयोगकर्ता-अनुकूल भी हो।

इसी कारण ऑफलाइन-फर्स्ट मॉडल की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जनगणना एप्लिकेशन ऐसे होने चाहिए जो इंटरनेट न होने पर भी डेटा संग्रह कर सकें और बाद में नेटवर्क उपलब्ध होने पर सर्वर से सिंक्रोनाइज हो जाएं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी निर्बाध डेटा संग्रह संभव हो सकेगा। साथ ही, स्थानीय भाषाओं में एप्लिकेशन और वॉयस-आधारित सहायता प्रणाली भी विकसित करनी होगी ताकि कम शिक्षित लोग भी इस प्रक्रिया में सहज रूप से भाग ले सकें। डिजिटल जनगणना के सामने दूसरी बड़ी चुनौती प्रवासी आबादी और असंगठित क्षेत्र के लोगों की सही गणना है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश ने देखा कि करोड़ों प्रवासी मजदूरों का विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप राहत और पुनर्वास कार्यों में भारी कठिनाइयां सामने आईं। भारत में बड़ी संख्या में लोग अस्थायी रूप से शहरों में काम करते हैं और अक्सर स्थायी पते से दूर रहते हैं। यदि जनगणना के दौरान वे अपने गांव या मूल निवास स्थान पर नहीं होंगे, तो उनकी गणना छूट सकती है। यही समस्या बेघर लोगों, फुटपाथ निवासियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों के साथ भी हो सकती है। इसलिए डिजिटल प्रणाली को इतनी लचीली बनाना होगा कि गतिशील आबादी

डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी



दों। वर्ष 1919 तक वे यहीं नियुक्त रहे। फिर वर्ष 1929 से 1949 तक खैरागढ विक्टोरिया हाईस्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में पढ़ाया। कुछ समय तक वे कांकेर जिले में भी अध्यापन करते रहे। वर्ष 1920 में वे सरस्वती के सहायक संपादक बने और एक वर्ष के भीतर ही 1921 में वे सरस्वती के प्रधान संपादक बना दिए गए। 1925 में उन्होंने स्वेच्छ से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1952 से 1956 तक उन्होंने महाकौशल के रविवारीय अंक का संपादन किया। 1955 से 1956 तक खैरागढ में ही रहकर सरस्वती का संपादन कार्य भी किया। 10 अगस्त 1959 को दिग्विजय कॉलेज राजनांदागंज में हिंदी के प्रोफेसर बने और जीवनवर्ष्यत यहीं कार्य करते रहे। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने

अपने साहित्यिक जीवन का शुभारम्भ कवि के रूप में किया था। 1916 से 1925 तक इनकी स्वच्छन्दतावादी प्रकृति की कविताएँ तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। बाद में शतदल नाम से इनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को वास्तविक ख्याति आलोचक तथा निबन्धकार के रूप में मिली। कुछ वर्षों तक छाया (इलाहाबाद) के भी सम्पादक रहे। बख्शी जी ने अपने जीवन में सम्मान भी खूब अर्जित किए। वर्ष 1969 में मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वाराका प्रसाद मिश्र द्वारा डी-लिट् की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्ष 1949 में उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मलेन द्वारा साहित्य वाचस्पति से विभूषित किया गया। वर्ष 28 दिसंबर 1971 को रायपुर के डीके अस्पताल में इस महान साहित्यकार ने अंतिम सांस ली ।

आज का इतिहास

- 1703 रूसी ज़ार पीटर I ने ग्रेट उत्तरी युद्ध के दौरान स्वीडन से इंग्रिड भूमि के बाद सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की।
- 1717 स्पेन ने न्यू ग्रेनेडा के विक्सरियल्टी के रूप में अपनी दक्षिण अमेरिकी उपनिवेशों को एकजुट किया।
- 1799 विंटरथुर का युद्ध : डेन्यूब की फांसीसी सेना से हाब्सबर्ग सेना ने उत्तर-पूर्व स्विट्जरलैंड के नियंत्रण को सुरक्षित रखा।
- 1805 नेपोलियन बोनापार्ट इटली के सम्राट बने।
- 1856 डॉक्टर विलियम पामर (रॉउली पॉयजनर) ने स्टैफोर्ड, इंग्लैंड में जहर का दोषी पाया गया।
- 1874 डोसलैंड ट्रेक का पहला समूह, राजनीतिक स्वतंत्रता और बेहतर स्थिति की तलाश में बोअर्स द्वारा खोजे गए विस्फोटों की एक श्रृंखला, अंगोला के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हो गया।
- 1895 ब्रिटिश आविष्कारक बीट अक्रेंस ने फिल्म प्रोजेक्टर का पेटेंट प्राप्त किया था।
- 1896 ज़ार निकोलस द्वितीय रूस के अंतिम सम्राट बने।
- 1908 खिलाफत दिवस- इस्लाम अलमदिया में खिलाफत की स्थापना का दिन। खिलाफत दिवस को 27 मई को अहमदिया मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसे खिलाफत के नाम से जाना जाता है।
- 1915 एचएमएस प्रिंसेस आइरीन 352 जिंदगियों के नुकसान के साथ यूनाइटेड किंगडम के शेरेंसे के विस्फोट से वंचित हो गई।
- 1919 कॉर्टिस NC-4 उड़ने वाली नाव पुर्तगाल के लिस्बन में पहुंची, जो अपनी शक्ति के तहत एक ट्रांसअटलांटिकलाइट को पूरा करने वाला पहला फिक्स्ड-विंग विमान बन गया।
- 1930 319 मीटर (1,047 फीट) की ऊंचाई पर स्थित, न्यू यॉर्क सिटी के क्रिसलरबीलडिंग को 11 महीने बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से आगे निकल जाने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में खोला गया था।
- 1935 यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने शेखर पोल्ट्रीकॉप में फैसला सुनाया। 1। संयुक्त राज्य अमेरिका, नई डील का राष्ट्रीय औद्योगिक रिकवरी अधिनियम, अमोनर घटक असंवैधानिक थे।
- 1942 चेक फाइटर्स ने प्राग में नाज़ियों का विरोध किया और घात लगाकर रैडच सिक्वीरिटी मेन ऑफिस के प्रमुख और बोहेमिया और मोराविया के रक्षक रेइनहार्ड हेर्डरिच को मार डाला।
- 1967 आस्ट्रेलियाई लोगों ने ऑस्ट्रेलियन संविधान को दो संशोधनों को मंजूरी दे दी, जिससे सरकार को स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों को लाभांवि्त करने और राष्ट्रीय जनगणना में गिनती करने की शक्ति मिली।

क्या सुधरेंगे भारत-अमेरिका के संबंध? मार्को रूबियो के दौरै के मायने

के एस तोमर

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत-अमेरिका संबंधों के एक नाजुक मोड़ पर भारत पहुंचे हैं। यों तो इस दौर के को हिंद-प्रशांत और क्राइ के प्रति वांशिंगटन की निरंतर प्रतिबद्धता के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इसका मकसद साफ था: उस रणनीतिक भरोसे को फिर से मजबूत करना, जो हाल के कुछ महीनों में कमजोर पड़ता दिख रहा था। भारतीय निर्यात के खिलाफ ट्रंप का आक्रामक टैरिफ नीति, पाकिस्तान के साथ वांशिंगटन की नई कूटनीतिक सक्रियता, अमेरिका की चीन रणनीति को लेकर अनिश्चितता और ईरान संकट से निपटने के अलग-अलग दृष्टिकोणों ने नई दिल्ली में बेचैनी बढ़ा दी थी। इसलिए रूबियो की चार-दिवसीय भारत यात्रा एक औपचारिक राजनयिक मुलाकात कम और आश्चर्य करने वाली कूटनीति का अभ्यास ज्यादा बनती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी से रूबियो की मुलाकात में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखलाओं व उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष जोर दिया गया है।

मगर इनके पीछे एक बड़ा भू-राजनीतिक उद्देश्य है: भारत को इस निष्कर्ष पर पहुंचाने से रोकना कि वांशिंगटन की रणनीतिक प्राथमिकताएं कहीं और खिसक रही हैं।

रूबियो भारत को यह भरोसा दिलाने आए हैं कि अमेरिका अब भी नई दिल्ली को अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए बेहद जरूरी मानता है। रूबियो ने प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस आने का ट्रंप का निमंत्रण भी दिया।

इस दौरै का मकसद टैरिफ विवादों की वजह से खराब हुए आर्थिक संबंधों को स्थिर करना भी है। हालांकि, अंतरिम व्यवस्था ने टैरिफ को कम कर दिया है, लेकिन एक व्यापक व्यापार समझौता अब भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। इसलिए, ऊर्जा व्यापार के विस्तार पर रूबियो का जोर केवल वाणिज्य तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य व्यापक संबंधों में तनाव को कम करना भी है। पश्चिम एशिया में पैदा हुई बाधाओं और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की अस्थिरता के चलते भारत को ऊर्जा के मामले में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रूबियो ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तर्क दिया कि अमेरिका की ऊर्जा आपूर्ति भारत के आयात में विविधता लाने और अस्थिर क्षेत्रों पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकती है। वांशिंगटन ऊर्जा निर्यात को भारत के साथ अपने बड़े व्यापार घाटे को कम करने के एक तरीके के रूप में भी देखता है।



नई दिल्ली पारंपरिक रूप से ईरान के साथ संतुलित संबंध बनाए हुए है, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा जरूरतें और कनेक्टिविटी से जुड़े हित (चाबहार परियोजना) हैं। भारत के सामने कठिन चुनौती है कि वह वांशिंगटन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को संतुलित रखते हुए, तेहरान के साथ स्वतंत्र जुड़ाव के लिए भी गुंजाइश बनाए रखे। मौजूदा ऊर्जा संकट अमेरिका और इराइल के ईरान के साथ बढ़ते टकराव के कारण ही ज्यादा गहरा गया है। जहां एक तरफ वांशिंगटन ऊर्जा के विकल्प पेश कर रहा है, वहीं अमेरिकी नीतियों ने ही उस अस्थिरता को बढ़ाने में भी योगदान दिया है, जिससे एशियाई ऊर्जा प्रवाह बाधित हो रहा है।

रूबियो की यात्रा इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नई दिल्ली में होने

की भारत यात्रा टल जाने से यह धारणा बनी कि %क्राइड का अनौपचारिक रूप से दर्जा घटा दिया गया है। इसलिए, नई दिल्ली में रूबियो की मौजूदगी का एक मकसद अंशतः ऐसी धारणाओं को मजबूत होने से रोकना है। भारत के लिए, क्राइ उपयोगी तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। नई दिल्ली क्षेत्रीय स्थिरता, तकनीकी साझेदारी और रक्षा सहयोग के लिए अमेरिका से एक स्थायी प्रतिबद्धता चाहती है। लेकिन ट्रंप की लेन-देन वाली विदेश नीति अक्सर अनिश्चितता पैदा करती है। भारत को इस बात की चिंता है कि वांशिंगटन का रणनीतिक ध्यान, घरेलू राजनीतिक समीकरणों या चीन के साथ बदलते संबंधों के आधार पर अचानक बदल सकता है। रूबियो ने हिंद-प्रशांत नीति में निरंतरता पर जोर देकर इन

शंकाओं को दूर करने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ प्रतीकात्मकता से भारत को आश्चस्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि ठोस आर्थिक और रणनीतिक प्रतिबद्धताएं न हों। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत के बाद, रूबियो ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों की रफ्तार कम नहीं हुई है और वे आने वाले वर्षों में और भी ज्यादा मजबूत होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि लंबे समय से लंबित द्विपक्षीय व्यापार समझौता जल्द ही पूरा हो जाएगा, और ज्यादातर बड़े वैश्विक मुद्दों पर दोनों देश रणनीतिक रूप से एकमत हैं।

गर्मजोशी के बावजूद, कई ढांचगत चुनौतियां भारत-अमेरिका संबंधों को जटिल बनाती आ रही हैं। पहला मुद्दा व्यापार है। ट्रंप की संरक्षणवादी नीति एक बड़ी अड़चन है। भारत को बाजार तक ज्यादा पहुंच, स्थिर टैरिफ नीतियां और अचानक लगने वाले व्यापारिक ढंड़ों से सुरक्षा चाहिए। वहीं अमेरिका अपने कृषि, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण उत्पादों के निर्यात के लिए व्यापक पहुंच चाहता है। दूसरी चुनौती रूस है। भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद वांशिंगटन में संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। हालांकि, अमेरिका ने अस्थायी रूप से अपना रुख नरम

किया है, लेकिन दबाव फिर से बढ़ सकता है। भारत ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा आपूर्ति के लिए रूस को अनिवार्य मानता है। तीसरा, आप्रवासन और वीजा नीतियां भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए लगातार परेशानी का सबब बनी हुई हैं। अमेरिका के ग्रीन कार्ड और एच1बी से जुड़े सख्त नियम भारतीयों में नाराजगी पैदा करते हैं, जो इन दोनों देशों के बीच सबसे मजबूत कड़ियों में से एक रहे हैं। चौथी चुनौती रणनीतिक स्वायत्तता है। भारत किसी भी कठोर चीन-विरोधी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वह जान कि किसी गठबंधन की बाध्यता के साझेदारी चाहता है। रूबियो की भारत यात्रा में चीन और पाकिस्तान, दोनों के लिए स्पष्ट भू-राजनीतिक संदेश भी निहित है। कुल मिलाकर, रूबियो की यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों में दिख रही दूरी को कम करने में सफल होती दिख रही है, लेकिन इससे उन संबंधों में मौजूद बुनियादी विरोधाभास खत्म नहीं हुए। आज इन संबंधों का आधार भावनात्मक रणनीतिक तालमेल कम और आपसी जरूरत ज्यादा है। एशिया में चीन की संतुलित करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है, जबकि भारत को अमेरिकी तकनीक, निवेश और भू-राजनीतिक समर्थन की जरूरत है।

आखिर विश्व, भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना क्यों चाहता है?

कमलेश पांडे

विश्व आज भारत की विकास यात्रा का हिस्सा इसलिए बनना चाहता है, क्योंकि भारत केवल बड़ा बाजार नहीं रहा, बल्कि वह अब यह देश वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक, सुरक्षा और मानव संसाधन का एक निर्णायक केंद्र बनता जा रहा है। खास बात यह है कि अब वह कई मामलों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस-जर्मनी-यूके जैसे यूरोपीय देशों से होड़ भी लेने लगा है। पहला, दुनिया को भारत में सबसे बड़ा बाजार दिख रहा है: भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहां तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल उपभोक्ता और विशाल युवा शक्ति वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर रही है। इसी कारण तकनीक, ई-कॉमर्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा क्षेत्रों में भारी विदेशी निवेश आ रहा है। दूसरा, चीन के विकल्प के रूप में भारत: अमेरिका-चीन तनाव और सप्लाय चेन संकट के बाद दुनिया चाइना प्लस वन रणनीति अपना रही है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब उत्पादन और निवेश का बड़ा हिस्सा भारत में स्थानांतरित करना चाहती हैं, क्योंकि वो भारत को एक स्थिर लोकतांत्रिक, कानूनी और विशाल श्रम-आधारित अर्थव्यवस्था माना जा रहा है। तीसरा, भारत की डिजिटल क्रांति ने दुनिया को प्रभावित किया: यूपीआई, आभार, डिजिटल गवर्नेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम और एआई आधारित सेवाओं ने भारत को डिजिटल पावर बना दिया है। चीूँकि दुनिया अब भारतीय डिजिटल मॉडल को कम लागत और बड़े पैमाने पर लागू होने वाली व्यवस्था के रूप में देख रही है। इसलिए भारत की ओर उनका झुकाव स्वाभाविक है। चौथा, भारत वैश्विक स्थिरता का नया स्तंभ बन रहा है: आज दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में भारत, अमेरिका से भी संबंध रखता है, रूस से भी, यूरोप, जापान, खाड़ी देशों और अफ्रीका से भी।

यही संतुलित कूटनीति भारत को विश्वसनीय शक्ति बनाती है। इसलिए अधिकांश देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। पांचवां, भारत का युवा मानव संसाधन दुनिया की जरूरत है: यूरोप, जापान और कई विकसित देशों में वृद्ध आबादी बढ़ रही है। इसके विपरीत भारत के पास विशाल युवा कार्यबल है। आईटी, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, एआई और सेवा क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छठवां, रक्षा और सामरिक शक्ति का बढ़ता प्रभाव: भारत तेजी से रक्षा उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, रक्षा कॉरिडोर, अंतरिक्ष कार्यक्रम और समुद्री शक्ति ने भारत को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया है। सातवां, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है: अफ्रीका, एशिया और विकासशील देशों को लगता है कि भारत पश्चिम और चीन- दोनों से अलग एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। जी-20, ब्रिक्स और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आठवां, निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक अवसर दिखते हैं: विश्व की बड़ी कंपनियां समझती हैं कि अगले 20-25 वर्षों तक भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, एआई, हरित तकनीक और विनिर्माण में विशाल अवसर मौजूद हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भले ही दुनिया भारत में अवसर तो देख रही है, पर साथ ही कुछ चिंताएं भी हैं: बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता, न्यायिक व प्रशासनिक देरी, राजनीतिक ध्रुवीकरण, और बुनियादी ढांचे की असमानता। यदि भारत इन चुनौतियों को संतुलित ढंग से संभाल लेता है, तो 21वां सदी में वह केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली महाशक्ति बन सकता है।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

जब मैं तिरुप्पुर के स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे मन में देश को लेकर कई सपने थे। मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठते थे-भारत अपनी महानता कब वापस पायेगा? विश्व मंच पर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कब उभरेगा? हमारे गरीब और वंचित भाई-बहनों को सम्मानजनक जीवन कब मिलेगा? मुझे खुशी है कि किशोरावस्था में मेरे मन में जो विचार थे, वे अब साकार हो रहे हैं। मैं अक्सर खुद को स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों की याद दिलाता था, 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको'। तमिलनाडु की धरती से स्वामी जी के ये शब्द हर व्यक्ति में देशभक्ति और समर्पण की भावना जगाने की अपार शक्ति रखते हैं। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि पिछले एक दशक में हमारा देश जबरदस्त ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

अब हमें अपनी आंखों के सामने तिरुवल्लुवर के इन शब्दों की सच्चाई देखने का अवसर मिल रहा है, 'जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं, वे ठीक वही हासिल करते हैं, जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है'। हम देख सकते हैं कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक दशक में भारत ने जो प्रगति हासिल की है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय कमजोर अर्थव्यवस्था माना जाने वाला हमारा देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ भारतवासी अल्पशिक गरीबों से बाहर निकलकर सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हुए हैं।

देश में गरीब और बेघर लोगों के लिए लगभग चार करोड़ पक्के घर बनाये जा चुके हैं। बारह करोड़ से अधिक



लोगों को पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। हमने खुले में शौच से मुक्त राष्ट्र बनने का संकल्प लिया था और केवल 60 महीनों के भीतर 60 करोड़ लोगों के लिए यह लक्ष्य हासिल कर दिखाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है, जिस पर 2।3 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। मैंने बचपन से ही गांवों में लोगों को इलाज की सुविधा न मिलने के कारण परेशान होते देखा है।

आज देश इस संकल्प के साथ आयुष्मान भारत योजना चला रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें। इसी का परिणाम है कि अब 44 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है। पिछले एक वर्ष में ही 2।5 करोड़ लोगों ने इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज प्राप्त किया है। आज हमारी नारी शक्ति के लिए देश के विकास में पूरी भागीदारी के अवसर खुल रहे हैं। तीन करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी बन चुकी हैं। कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान एवं तकनीक से लेकर अंतरिक्ष तकनीक तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करायी है।

अब महिलाएं सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन प्राप्त कर रही हैं और युद्धक भूमिकाओं में भी भाग ले रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में उनकी भागीदारी को और मजबूत करेगा। युवाओं के लिए पिछले दस वर्षों में 13 नये आइआइटि स्थापित किये गये हैं, जिससे देश में इनकी

संख्या बढ़कर 23 हो गयी है। आइआइएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गयी है। एम्स की संख्या सात से बढ़कर 23 हो चुकी है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 37 से बढ़कर 823 हो गयी है। मेडिकल छात्रों के लिए सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,29,603 हो गयी है।

भारतीय रेलवे का लगभग 99 फीसदी विद्युतीकरण हो चुका है। देशभर में 164 बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने रेल यात्रा के नये युग की शुरुआत की है। हवाई अड्डों की संख्या भी 74 से बढ़कर 163 हो गयी है और उड़ान योजना के तहत आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है। तमिलनाडु के लिए रेलवे बजट का आवंटन एक दशक पहले लगभग 880 करोड़ था, जो बढ़कर 2026₹27 में 7,600 करोड़ रुपये हो गया है। रामेश्वरम और पंबन के बीच नया पंबन ब्रिज बनाया गया है, जो देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। चाहे चिनाव ब्रिज हो या बोंगीबील पुल, भारत अब आधुनिक बुनियादी ढांचे के नये आयाम स्थापित कर रहा है। देशभर में विश्व स्तरीय चार-लेन और आठ-लेन की सड़कों के साथ सुदूर गांवों तक सड़क संपर्क को मजबूती से विकसित किया गया है।

तमिलनाडु में पिछले 10 वर्षों में 4,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये गये हैं। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 10 वर्षों में लगभग 7,200 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। ये सभी विकास कार्य 'प्रगति' के तहत प्रधानमंत्री की करीबी निगरानी के कारण संभव हो पाये हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को देश की 'अष्टलक्ष्मी' कहा था। हाल ही में जब मैंने नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम का दौरा किया, तब वहां परिवहन और बुनियादी ढांचे में जबरदस्त सुधार देखने को मिला।

हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक भारत एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बने और दुनिया का मार्गदर्शन करने की स्थिति में पहुंचे। आइए, हम सब मिलकर अपनी कड़ी मेहनत से विकसित भारत का निर्माण करें।

क्या सच में यूरेनियम सौंपने को तैयार है ईरान?

अभिनव आकाश

मिडिल ईस्ट में जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति थी उससे पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ था। लेकिन अब क्या एक बड़े युद्ध के मुहाने से वापस लौट रहे हैं? क्या वही ईरान जिसने सालों तक अमेरिका के सामने झुकने से इंकार किया। अब अपना सबसे बड़ा हथियार एनरिचड यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का वो लंबा पोस्ट सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि आने वाले मिडिल ईस्ट के रिश्तों का एक रिसेट का संकेत माना जाए। कहा गया कि ईरान ने अपने हाईली इनरडू यूरेनियम का स्टॉक छोड़ने पर हामी भर दी है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ अमेरिका ईरान के रिश्तों में नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जाएगा। क्योंकि पिछले कई महीनों से हालात ऐसे थे कि कभी भी बड़ा युद्ध छिड़ सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जल्द ऐसा समझौता हो सकता है जिससे जंग रुक सकती है और हॉर्मोज स्टेटे फिर से पूरी तरह खुल सकता है। आज के एमआरआई में बताएंगे कि आखिर अमेरिका बार-बार ईरान के यूरेनियम पर इतना जोर क्यों दे रहा था? स्टेटे ऑफ हॉर्मस क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या ईरान हकीकत में अपना संबंधित यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा? क्योंकि अगर यह डील सच में हो गई तो इसका असर तेल से लेकर भारत से लेकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से पड़ने वाला है।

पिछले कई महीनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ रहा है। 2026 में हालात यहां तक पहुंच चुके कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और न्यूक्लियर टारगैट्स पर स्ट्राइक कर दिया। जवाब में ईरान ने स्टेटे ऑफ होर्मुज पर दबाव बढ़ाया। अब यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल को सप्लाई दी जाती है। मतलब कि अगर होर्मुज बंद तो पूरी दुनिया में तेल महंगा, बाजार अलान और आर्थिक संकट शुरू हो जाएगा। लेकिन अब अचानक तस्वीर अर्धों ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा बयान जारी किया और बयान जारी करके यह दावा किया कि ईरान पीस डील में लार्जली नेगोशिएटेड हो हो चुका है। यानी कि समझौता लगभग तय है। अब रिपोर्ट्स की अगर मानें तो तमाम अलग-अलग तरीके की बातें सामने आई



और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील के तहत स्टेटे ऑफ होर्मुज खोला जा सकता है। सीज फायर आगे बढ़ सकता है। ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिल सकती है और सबसे बड़ा मुद्दा संबंधित यूरेनियम का है। ह का अनुमान है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर 2.6% रह सकती है। कोरोना के पहले यह एवरेज 3व और 2008 के वित्तीय संकट के पहले 4.4% थी। वहीं, डूब्स का आकलन तो और भी डराने वाला है। अगर जल्द सप्लाई चेन बहाल नहीं हुई, तो अगले साल ग्लोबल ग्रोथ गिरकर केवल 2% रह सकती है, जबकि महंगाई 6% पर पहुंच जाएगी।

अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच जो बड़े समझौते की तैयारी हो रही है उसमें ईरान अपने उस यूरेनियम स्टॉक को छोड़ सकता है जिसे हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 30 से 60 दिनों में इस पर बातचीत होगी कि ईरान अपने यूरेनियम का क्या करेगा। अभी सिर्फ शुरुआती सहमति बनी है। यानी यह तय नहीं हुआ है कि यूरेनियम देश के बाहर भेजा जाएगा या उसकी क्षमता कम की जाएगी या उसे किसी और तरीके से बेअसर किया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसकी टेक्निकल डिटेल्स बाद की न्यूक्लियर मुद्दे पर होने वाली बातचीत में तय होगी। यह बदलाव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में ईरानी सूत्रों ने दावा किया था कि देश के सर्वोच्च नेता यानी कि मौजतबा खामेनई ने निर्देश दिया था कि यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इस समय ईरान के पास करीब 400 किलो यूरेनियम है जिसे 60% तक एनरच किया जा चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह

स्तर परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब होता है। यूरेनियम को एक प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे उसमें काम आने वाला हिस्सा बढ़ जाता है। इसे ही यूरेनियम एनरचमेंट कहते हैं।

इजराइल भी लंबे समय से कहता रहा है कि अगर इस यूरेनियम को और एनरिच किया गया तो उससे कई परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वजह थी कि बातचीत में सबसे बड़ा अड़ुंगा यही मुद्दा बना हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता था कि यूरेनियम वाला मुद्दा बाद में देखा जाए। लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया था कि शुरुआती समझौते में ही इस पर कम से कम शुरुआती वादा तो किया ही जाना चाहिए। वरना बातचीत खत्म हो सकती है और सैन्य कारवाई फिर से शुरू हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हाल के दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के यूरेनियम स्टॉक पर हमला करने के कई विकल्प तैयार किए थे। माना जाता है कि ईरान का काफी यूरेनियम न्यूक्लियर फैसिलिटी के नीचे जमीन के अंदर रखा गया है। इस ठिकाने पर पिछले साल अमेरिकी टॉम्होकर मिसाइलों से हमला किया गया था। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ऐसे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करने का विकल्प भी तैयार किया था जो जमीन के अंदर बने ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक समय पर ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल के संयुक्त कमांडो ऑपरेशन पर भी विचार किया था।

यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसी के पीछे अमेरिका बार-बार ईरान के ऊपर दबाव भी बना रहा है। क्योंकि फिलहाल अभी जो यह युद्ध रुका है, यह सिर्फ टेंपरेरी पाँज है। तूफान से पहले की शांति भी इसे कहा जा सकता है। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि किस तरीके से सीज फायर की तरफ बढ़ते हैं। क्या ईरान सच में अपने संबंधित यूरेनियम को सौंप देगा? क्या अमेरिका जो लंबा चौड़ा पोस्ट लिख रहा है कि अब शायद हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा क्लोज टू सीज फायर की डील पर पहुंच चुके हैं। वो हकीकत है। इन सारी बातों को देखना होगा। ये परिस्थितियां भारत के लिए भी बुरी हैं। इरानमी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ईंधन चाहिए, जिसके लिए भारत बुरी तरह से आयात पर निर्भर है। पेट्रोल-डीजल की खरीद में विविधता के बावजूद संकट महसूस हो रहा है, और तभी पिछले कुछ अरसे में तीन बार दाम बढ़ाने पड़े हैं।

नक्सलवाद की ढहती दीवारें और मध्यप्रदेश की रणनीतिक जीत

कृष्णमोहन झा

भारत में नक्सलवाद लंबे समय तक आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। जंगलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला यह लाल आतंक केवल हिंसा से सीमित नहीं था, बल्कि उसने विकास, लोकतंत्र और जनविश्वास को भी प्रभावित किया।

मध्यप्रदेश का बालाघाट क्षेत्र भी वर्षों तक इस चुनौती से जूझता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। मध्यप्रदेश ने नक्सलवाद के खिलाफ जिस प्रभावी रणनीति और दृढ़ संकल्प के साथ अभियान चलाया है, वह आज पूरे देश के लिए एक मॉडल बनता दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन के पीछे मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्पष्ट नेतृत्व और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी गंभीर सोच महत्वपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लगातार यह संदेश दिया कि प्रदेश में विकास और सुरक्षा साथ-साथ चलेंगे तथा नक्सलवाद जैसी चुनौती को किसी भी स्थिति में बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा एजेंसियों को बेहतर समन्वय, संसाधन और आधुनिक रणनीति के साथ कार्य करने का अवसर मिला।

इसी के साथ पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के नेतृत्व ने नक्सल विरोधी अभियान को नई दिशा दी। उन्होंने केवल आप्रेशन आधारित दृष्टिकोण तक सीमित न रहकर इंटील्रेंस नेटवर्क को मजबूत करने, सीमावर्ती राज्यों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने और हॉक फोर्स को अत्याधुनिक प्रशिक्षण एवं संसाधनों से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश पुलिस ने नक्सली गतिविधियों पर लगातार प्रभावी प्रहार किए और उनके नेटवर्क को कमजोर करने में सफलता प्राप्त की।

मध्यप्रदेश पुलिस को इसी उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बस्तर में आयोजित उद्घाटन बस्तर कार्यक्रम में डीजीपी कैलाश मकवाना, वरिष्ठ

अधिकारियों और हॉक फोर्स के जवानों को सम्मानित किया। यह सम्मान नक्सल उन्मूलन अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। पिछले दो वर्षों की उपलब्धियां बताती हैं कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच सात बड़ी मुठभेड़ें हुईं, जिनमें कई इनामी नक्सली मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। वर्ष 2025 में यह अभियान और अधिक प्रभावी हुआ, जब दस बड़ी मुठभेड़ों में दस माओवादी ढेर किए गए। यह किसी एक वर्ष में मारे गए माओवादियों की सर्वाधिक संख्या मानी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नक्सली संगठनों का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। कई बड़े माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया है। यह केवल सुरक्षा बलों की सामरिक सफलता नहीं, बल्कि वैचारिक स्तर पर भी नक्सलवाद की पराजय का संकेत है।

हालांकि यह सफलता आसान नहीं थी। 1991 से लेकर अब तक नक्सलियों ने कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया, जिनमें अनेक पुलिसकर्मी शहीद हुए। लैंडमाइन ब्लास्ट, घात लगाकर किए गए हमले और राजनीतिक हत्याओं ने प्रदेश को लंबे समय तक प्रभावित किया। लेकिन सुरक्षा बलों के साहस और नेतृत्व की दृढ़ता ने परिस्थितियों को बदल दिया। आज मध्यप्रदेश में नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है। जिन क्षेत्रों में कभी भय और बारूद का वातावरण था, वहां अब विकास, शिक्षा और विश्वास की नई रोशनी दिखाई दे रही है। यह उपलब्धि केवल पुलिस या सरकार की सफलता नहीं, बल्कि लोकतंत्र और जनविश्वास की विजय है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन, डीजीपी कैलाश मकवाना के कुशल नेतृत्व और हॉक फोर्स के जवानों के अदम्य साहस ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, रणनीतिक सोच और जमीनी कार्रवाई एक साथ हों, तो सबसे कठिन आंतरिक चुनौती पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।



एसी के साथ पंखा चलाना सही है या गलत?

बिजली बिल बचाने का आसान तरीका

गर्मी के मौसम में कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए लोग अक्सर एसी और पंखा एक साथ चला लेते हैं। हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या एसी और फैन को साथ चलाना सही है या इससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि पंखा चलाने से एसी पर दबाव बढ़ता है और मशीन खराब हो सकती है। लेकिन सच इसके बिल्कुल

उलट है। एसी और पंखा एक-दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि अच्छे साथी हैं। अगर इन्हें सही तरीके से साथ इस्तेमाल किया जाए तो कमरा जल्दी ठंडा होता है, एसी पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता और बिली की खपत भी कम हो जसकती है।

कूलिंग क्यों नहीं होती
गर्मियों में कमरा काफी गर्म रहता है और ऐसे में अगर आप एसी 16-21-24 पर चलाते हैं, तो उस पर लोड ज्यादा पड़ता है और कूलिंग मन-मुताबिक नहीं होती। जब एसी पर लोड बढ़ेगा तब बिजली की खपत भी होगी और यही

कारण है कि आपका बिल ज्यादा आता है।
एसी-पंखा साथ चलाने से क्या होगा?
मान लीजिए कि आपने सिर्फ एसी चलाया हुआ है, जो कमरे की हवा को धीरे-धीरे ठंडा कर रहा है। इस प्रोसेस में समय लगेगा और करीब आधे-1 घंटे के बाद कमरा ढंग से ठंडा होगा। अगर फौरन चिल्लड करना चाहेंगे तो एसी को लो टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साथ में 2-3 नंबर पर पंखा चला लेते हैं, तो ये कमरे की कोने-कोने की हवा को ठंडा करने में जल्दी मदद करेगा। अगर आप 24 नंबर पर एसी चला रहे हैं और साथ में 3 नंबर पर पंखा, तो कमरा जल्दी ठंडा होगा और एसी पर ज्यादा लोड नहीं आएगा।

बिजली बिल कैसे बचेगा
जब आप कम स्पीड में एसी चलाएंगे तो बिजली का बिल खुद ही कम आएगा और एयर कंडीशनर की मशीन पर लोड भी कम पड़ेगा। पंखे के साथ आप एसी का टेम्परेचर 24-25-26 पर रख सकते हैं और ऐसे में आपका रूम बिल्कुल चिल्लड हो जाएगा।
रात में सुकून की नींद
कई लोग एसी रातभर चलाते हैं, तो कमरे में नमी बनी रहती है या अजीब सी महक के कारण सो नहीं पाते। पंखा साथ में चलाते हैं, तो एसी से कमरे में नमी नहीं होगी और चैन की नींद आएगी। पंखे की हवा से एसी कमरे को कुछ ही देर में ठंडा कर देगा और नमी गायब हो जाएगी।

कूलिंग टिप्स
अगर आपका कमरा काफी बड़ा है, तब आप ये तरीका अपनाकर देखें। अगर कमरा छोटा। ये दोनों चीजें आपको बेहतर कंफर्म और बेलेन्सड है, तो एसी को 22 पर सेट करके कुछ देर के लिए चलाएं और पंखा बंद रखें। इसके बाद हल्का पंखा चलाकर एसी का टेम्परेचर कम करें। साथ ही एसी चलाने से पहले कमरे की खिड़कियां, दरवाजे बंद करें, जिससे हवा बाहर न जाए और कमरा जल्दी कूल होकूलिंग देंगे।



पतले दूध में मलाई पतली जमती है या फिर जम ही नहीं पाती। अगर आप भी फुल क्रीम दूध नहीं खरीदते हैं, तो हम आपको पतले दूध में गाढ़ी मलाई जमाने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। इसके बाद आप डेयरी हो या फिर बाजार का पतला दूध सभी में रोटी जितनी मोटी मलाई जमा लेंगे।

बाजार वाले पतले दूध से भी निकलेगी रोटी जितनी मोटी मलाई!

दूध हर घर में आता है और उससे मलाई निकालकर घी भी बनाया जाता है। कई लोग मलाई ऐसे ही निकालते हैं, जो खाने या फिर कुछ और बनाने के काम में आए। लेकिन अगर आप डेयरी या फिर बाजार से पतला वाला दूध खरीदते हैं, तो मोटी मलाई का निशान दूर-दूर तक नहीं रहता। इन दूध में पतली मलाई जमती है, जो किसी काम की नहीं होती। अगर आप भी पतली मलाई जमने से परेशान रहती हैं, तो अब एक ट्रिक अपनाकर पतले और पानी मिले दूध से भी रोटी जितनी मोटी मलाई जमा सकती हैं। कई महिलाएं दूध में सिर्फ 1 चम्मच खास चीज मिलाकर मलाई को ज्यादा गाढ़ा और मोटा बना लेती हैं। खास बात ये है कि इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।

दूध कैसे उबालें
अक्सर हम दूध को तेज आंच पर चढ़ा देते हैं और एक उबाल आते ही गैस बंद कर देते हैं। ऐसा करने से दूध अच्छी तरह पक नहीं पाता, और यही वजह होती है कि उस पर मोटी मलाई नहीं जमती। अगर आप चाहती हैं कि दूध पर बाजार जैसी गाढ़ी मलाई जमे, तो सबसे पहले दूध को हमेशा धीमी आंच पर पकाना शुरू करें। भले ही इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगे, लेकिन धीमी आंच पर दूध अच्छे से खोलता है और उसका टेक्सचर

भी बेहतर हो जाता है। जब दूध धीरे-धीरे पकते हुए पहली उबाल लेने लगे, तभी आपको अपनी सीक्रेट ट्रिक अपनानी है। इसी स्टेज पर थोड़ा-सा मिल्क पाउडर मिलाने से दूध में फेट और सॉलिड्स बढ़ जाते हैं, जिससे बाद में मलाई ज्यादा मोटी और गाढ़ी जमती है। यही छोटा-सा तरीका पतले दूध को भी मलाईदार बना देता है।

क्या मिलाना है
दूध जब हल्की पहली उबाल लेने लगे, तब उसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर मिला दें। मिल्क पाउडर का स्वाद दूध में महसूस नहीं होगा, लेकिन इससे मलाई काफी गाढ़ी और मोटी जमेगी। मिल्क पाउडर डालने के बाद दूध को चम्मच से बार-बार न चलाएं और ठंडा होने के तुरंत आने दें। इसके बाद गैस बंद कर दें और दूध को ठंडा होने दें। फिर इसे फ्रिज में रख दें। कुछ घंटे बाद आप देखेंगे कि



पतले दूध पर भी मोटी मलाई जमकर ऊपर तैर रही है।
क्यों काम करती है ये ट्रिक?

मिल्क पाउडर दूध में फेट और सॉलिड्स बढ़ाने का काम करता है। इसी वजह से मलाई ज्यादा और मोटी जमती है। अगर आप फुल क्रीम दूध नहीं लेते, तो यह तरीका सबसे आसान और असरदार है। बस ध्यान रखें कि दूध को बार-बार न चलाएं और ठंडा होने के तुरंत बाद फ्रिज में रख दें। यह तरीका आप डेयरी वाले दूध के साथ भी आसानी से आजमा सकती हैं।

नींबू के छिलकों से आपकी तुलसी होगी घनी और स्वस्थ!



घर में लगी तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि आस्था, सेहत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी तुलसी ठीक से बढ़ नहीं रही, पतियां पीली पड़ जाती हैं या पौधा बार-बार सूखने लगता है। ऐसे में लोग महंगे फर्टिलाइजर और केमिकल का सहारा लेते हैं, जबकि इसका आसान और मुफ्त समाधान आपके किचन में ही मौजूद होता है नींबू के छिलके।

क्यों खास है नींबू के छिलकों का इस्तेमाल?
अक्सर हम नींबू का रस निकालने के बाद उसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन यही छिलके तुलसी के लिए किसी नेचुरल टॉनिक से कम नहीं हैं। इनमें मौजूद सिट्रस ऑयल, एंटी-बैक्टीरियल गुण और पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

कीड़ों से बचाने का प्राकृतिक तरीका
तुलसी के पौधे पर छोटे-छोटे कीड़े या चींटियां लग जाना एक आम समस्या है। नींबू के छिलकों की तेज खुशबू इन कीड़ों को दूर भगाने में मदद करती है। जब आप इन्हें मिट्टी में डालते हैं, तो यह एक नेचुरल कीटनाशक की तरह काम करते हैं और पौधे को सुरक्षित रखते हैं।

मिट्टी को बनाते हैं ज्यादा उपजाऊ
तुलसी के पौधे को हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। नींबू के छिलके मिट्टी के pH स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे जड़ें पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाती हैं। इसका असर यह होता है कि पौधा तेजी से बढ़ता है और ज्यादा हरा-भरा दिखाई देता है।

फंगस और सड़न से बचाव
अधिक पानी या नमी के कारण तुलसी की जड़ों में फंगस लगने की समस्या हो सकती है। नींबू के छिलकों में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण इस समस्या को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही, यह मिट्टी में आने वाली बदबू को भी दूर कर देते हैं और उसे ताजा बनाए रखते हैं।

इस्तेमाल करने के आसान तरीके
नींबू के छिलकों का सही फायदा पाने के लिए इन्हें सीधे इस्तेमाल करने के बजाय कुछ आसान तरीकों को अपनाना बेहतर होता है। आप छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर गमले की मिट्टी में हल्का दबा सकते हैं। दूसरा तरीका है, इन्हें 2-3 दिन पानी में भिगोकर उस पानी को छान लें और पौधे में डालें यह एक लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करना हो, तो छिलकों को सुखाकर पीस लें और महीने में एक बार मिट्टी में मिला दें।

इस्तेमाल करते समय रखें ये सावधानियां
ध्यान रखें कि नींबू के छिलकों का ज्यादा इस्तेमाल भी नुकसान कर सकता है। हफ्ते में एक बार से ज्यादा इसका प्रयोग न करें। अगर मिट्टी पहले से ज्यादा एसिडिक है, तो इसका उपयोग करने से बचें। साथ ही, छिलकों को हमेशा मिट्टी के अंदर दबाकर रखें, ताकि ऊपर फंगस न लगे।



गर्मियों में शिशुओं की सेहत का रखें ख्याल, खिलाएं ये खाना

गर्मियों का मौसम में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, खास कर छोटे बच्चों का। ऐसे में पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए, उन्हें गर्मियों में खाने के लिए क्या दिया जाए। जिससे बच्चों का शरीर स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहे। गर्मियों में शिशुओं (0-1 साल) का आहार हल्का, पोष्टिक और शरीर को ठंडक देने वाला होना चाहिए। लेकिन क्या खिलाना है, यह बच्चे की उम्र (6 महीने से कम या ज्यादा) पर निर्भर करता है। चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि बच्चों को गर्मी में क्या खिलाना चाहिए?

छोटे बच्चों को गर्मियों में कैसा

खाना खिलाएं?
गर्मियों में शिशुओं को हल्का, पोष्टिक और शरीर को ठंडक देने वाला आहार खिलाना चाहिए। एक्सपर्ट के अनुसार, गर्मी के मौसम में बच्चों को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए हल्के, आसानी से पचने वाले और पानी से भरपूर खाने की जरूरत होती है। बच्चों को भारी खाना नहीं खिलाना चाहिए, उन्हें हल्का और जल्दी पचने वाला खाना खिलाना चाहिए।

6 महीने से कम उम्र के बच्चों को क्या दें?

एक्सपर्ट के मुताबिक, 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए तो मां का दूध ही

काफी होता है। क्योंकि इसमें पहले से ही सही मात्रा में पानी और पोषक तत्व होते हैं। जब तक डॉक्टर शिशु को पानी पिलाने की सलाह न दें, उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं देना चाहिए।
6 महीने से ज्यादा के बच्चों को क्या खिलाना चाहिए?
जब बच्चा 6 महीने से ज्यादा का हो जाए तो आप धीरे-धीरे ठोस आहार शुरू कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक, चावल का पानी, मूंग दाल की पतली खिचड़ी, दलिया (हल्का और पतला), फल (अच्छी तरह मेश करके), केला, सेब (उबालकर या स्टीम करके), पपीता, तरबूज (बीज

निकालकर, कम मात्रा में) आप बच्चों को ये आहार दे सकते हैं।
बच्चों को सब्जियां खिलाएं
बच्चों को उबली और मेश की हुई सब्जियां खिलानी चाहिए। जैसे, गाजर, लौकी, कद्दू, आलू।
बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए ये भी दें
बच्चों को गर्मी में उबला और ठंडा किया हुआ पानी (6 महीने बाद), घर का बना छाछ (बहुत पतला, थोड़ा सा), नारियल पानी (कम मात्रा में, डॉक्टर की सलाह से) दें।

मुसलमानों पर थोपा जा रहा हिंदू कानून: ओवैसी

हैदराबाद। असम विधानसभा में हिमंत बिस्वा सरमा सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक पेश होने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूसीसी कानून को मुसलमानों पर बैकडोर से हिंदू कानून थोपने का प्रयास बताया। असम, गुजरात, गोवा और उत्तराखंड के बाद चौथा भाजपा शासित राज्य बन गया है, जहां समान नागरिक संहिता अपनाने की प्रक्रिया शुरू की है। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह विधेयक मुस्लिम पर्सनल कानूनों पर सीधा हमला और उनके संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। उन्होंने लिखा कि उत्तराधिकार, विरासत और तलाक जैसे महत्वपूर्ण मामलों में हिंदू सिद्धांतों को जबरन थोपा जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ हिंदू संस्कृति को संरक्षित करना है, जबकि मुसलमानों को इन कथित समान कानूनों को मानने के लिए मजबूर किया।

चार दिन यात्रा पूरी कर मार्को रूबियो आर्मेनिया रवाना

नई दिल्ली। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो चार दिन का भारत दौरा पूरा कर आर्मेनिया रवाना हो गए। मंगलवार को क्राड बैठक में हिस्सा लेने के बाद वह आर्मेनिया रवाना हुए। उनकी यात्रा से पहले अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी कर बताया कि रूबियो 26 मई को कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए अलग-अलग बैठकें करेंगे। दौरे के दौरान रूबियो की मुलाकात आर्मेनियाई के विदेश मंत्री अरारात मीरजोयान से होगी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान जारी किए जाने की भी उम्मीद है। दूतावास के मुताबिक कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच कुछ द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी शामिल हैं। बता दें रूबियो ने भारत की यात्रा 23 मई को कोलकाता से शुरू हुई थी। इसके बाद वो नई दिल्ली पहुंचे, यहां पर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की, पीएम मोदी से भी मुलाकात की, फिर पत्नी जेनेट डी. रूबियो के साथ ताजमहल का दीदार किया।

पीएम मोदी को सीएम योगी ने बधाई दी, कहा- नए भारत की नींव रखने वाले

नई दिल्ली। साल 2014 में 26 मई को नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में गरीब कल्याण को सर्वोपरि प्राथमिकता मिली है, वहीं जनभागीदारी ने विकास को एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक के रूप में सेवा, सुशासन और लोक-कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई। इन वर्षों में अंत्योदय आत्मनिर्भरता की शक्ति में परिवर्तित हुआ है।

नीलम मीणा बनीं पश्चिम बंगाल की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कोलकाता। 1998 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीलम मीना को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से जारी आदेश के तहत उनकी नियुक्ति की घोषणा की गई।यह नियुक्ति पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद की गई है। नीलम मीणा प्रशासनिक सेवा में लंबे अनुभव रखती हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, डिप्टी चेयरमैन, प्राइवेट सेक्रेटरी, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त निदेशक जैसे कई प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी नियुक्ति को आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निर्माणाधीन टैंक में उतरे 6 मजदूरों की गई जान

भुवनेश्वर । ओडिशा के कालाहांडी जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस के कारण दम घुटने से यह हादसा हुआ। घटना मदनपुर-रामपुर थाना क्षेत्र के गौड़ कार्लाखुंटा गांव में हुई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, सभी मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए थे। वे सेप्टिक टैंक के भीतर लगे सेंटिंग सामग्री को निकालने के लिए अंदर उतरे थे। इसी दौरान टैंक में मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आने से एक के बाद एक मजदूर बेहोश होकर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब एक व्यक्ति टैंक के भीतर अचेत हुआ तो उसे बचाने के प्रयास में अन्य लोग भी अंदर गए, लेकिन वे भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। देखते ही देखते छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। इसके बाद बचाव अभियान चलाकर सभी शवों को टैंक से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है।

क्वाड विदेश मंत्रियों की महाबैठक, एस. जयशंकर बोले-

वैश्विक विकास और स्थिरता का मुख्य इंजन बना रहे हिंद-प्रशांत क्षेत्र

नईदिल्ली। चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) देशों के विदेश मंत्रियों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने दौड़क कहा कि हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र को वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रमुख वाहक बने रहना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए सदस्य देशों के बीच “विश्वसनीय और पारदर्शी” साझेदारी का पुरजोर आह्वान किया। इस उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिस्सा लिया।

दिल्ली में जयशंकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भाग लिया। यह बैठक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता को लेकर दुनिया भर में बढ़ती चिंताओं के बीच हुई।

जयशंकर ने टेलीविजन पर



प्रसारित अपने प्रारंभिक बयान में कहा, “हमारा ध्यान स्पष्ट रूप से हिंद-प्रशांत पर रहेगा, जो क्वाड की विशिष्ट सीमा है।” उन्होंने कहा, “वैश्विक स्तर पर हमें आपूर्ति शृंखला की मजबूती, संपर्क मार्गों में अवरोध, विनिर्माण और संसाधनों के अत्यधिक केंद्रीकरण तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। इनमें से हर मुद्दा अधिक साझेदारियों की आवश्यकता को और मजबूत आधार देता है।” जयशंकर ने बिना विस्तार में जाए हिंद-प्रशांत क्षेत्र की संभावित “चिंताओं” का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, “इसके लिए रणनीतिक विश्वास को मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्थिक विकल्पों को बढ़ावा देना और सहयोगी मजबूत भावना को पोषित करना जरूरी होगा। यह सब विश्वसनीय और पारदर्शी साझेदारियों को बढ़ावा देकर सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है।” विदेश मंत्री ने

कहा, “समुद्री लोकतंत्रों, बहुलवादी समाजों और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हम एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के प्रति साझा जिम्मेदारी रखते हैं। यह क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रमुख वाहक बना रहना चाहिए।” ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉंग ने क्वाड को यथासंभव मजबूत और प्रभावी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम क्वाड की गति को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और एक शांतिपूर्ण, स्थिर तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र चाहते हैं।

रूबियो ने कहा कि दुनिया भर में हाल की घटनाओं के कारण वे क्षेत्र और भी प्रासंगिक हो गए हैं, जिनमें क्वाड मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्वाड ऊर्जा सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और महत्वपूर्ण खनिजों सहित दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से कुछ का समाधान कर सकता है।

स्टेल प्रमुख समाचार

सनराइजर्स के खिलाफ रॉयल्स का मुकाबला आज

मुळोंपुर। अपने विस्फोटक बल्लेबाजों की मौजूदगी से बेहद मजबूत नजर आ रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बुधवार को यहां जब इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी की तो उसे 15 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी और तेज तर्रार गेंदबाज जोफा आर्चर से सावधान रहना होगा। सनराइजर्स की टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी लेकिन उसने दूसरे चरण में लय हासिल कर ली।

नियमित कप्तान पैट कर्मिस के आने से भी टीम को काफी फायदा हुआ, क्योंकि उसने अपने इन आखिरी सात मैचों में से पांच में जीत हासिल की। सनराइजर्स ने लीग चरण में राजस्थान रॉयल्स को दो बार हराया था और इस तरह से कर्मिस और उनकी टीम को बहुत अधिक दबाव वाले नॉकआउट मुकाबले में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी। रॉयल्स के कप्तान रियाग पराग ने खुद स्वीकार किया कि उनकी टीम को लीग चरण के आखिरी दिन तक इंतजार करने से बहुत पहले ही क्वालीफाई कर लेना चाहिए था, लेकिन अब जबकि टीम वहां पहुंच गई है तब वह आगे बढ़ने के लिए बेताब होगी। रॉयल्स के शीर्ष क्रम में सूर्यवंशी (583 रन), यशस्वी जायसवाल (397) और ध्रुव जुरेल (458) ने सर्वाधिक रन बनाए हैं।

सनराइजर्स की तरफ से भी शीर्ष क्रम के तीन बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा (563 रन), ट्रेविंस हेड (393) और ईशान किशन (569) ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन नंबर चार पर बल्लेबाजी करने वाले हेनरिक क्लासेन (606) का विशेष रूप से उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अब तक शानदार बल्लेबाजी की है। दोनों टीमों के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की विस्फोटक क्षमता से बावजूद जायसवाल और हेड के प्रदर्शन में उतनी निरंतरता नहीं रही है जितना वे चाहते थे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 479 अंक फिसला निफ्टी 23,914 पर बंद

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को कमजोरी देखने को मिली। दक्षिणी ईरान में अमेरिका की ओर से की गई रक्षात्मक कार्रवाई के बाद शांति समझौते की उम्मीदों पर असर पड़ा, जिससे वैश्विक निवेश धारणा कमजोर हुई। इसका सीधा प्रभाव घरेलू बाजारों पर भी पड़ा और प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 50 118.00 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,913.70 पर बंद हुआ। वहीं बीएसई सेंसेक्स 479.26 अंक यानी 0.63 प्रतिशत टूटकर 76,009.70 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज, विप्रो और भारती एयरटेल सबसे ज्यादा नुकसान में रहने वाले शेयरों में शामिल रहे। इन स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने मुख्य सूचकांकों से अलग प्रदर्शन किया।

प्रीमियर एनर्जीज में 5.3% हिस्सेदारी खुले बाजार में 2,291 करोड़ रुपए में बिकी

नई दिल्ली। नोमुरा एसेट मैनेजमेंट और कैपिटल ग्रुप जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड में प्रवर्तकों से 5.3 प्रतिशत हिस्सेदारी 2,291 करोड़ रुपए में खुले बाजार लेनदेन के माध्यम से खरीद ली है। तब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गोर ने मजाक में पूछा, नरेंद्र भाई, आप यह फीमेल-फीमेल क्या कह रहे हैं? इस फीमेल-ईमेल से क्या होगा? इस पर सब हंस पड़े और कुछ लोगों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव भी थे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद नरेंद्र भाई ने ईमेल और तकनीक के महत्व पर जोर दिया। चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने दूसरों से बहुत पहले यह समझ लिया था कि अगर भारत के भविष्य को आकार

खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की 2025-26 में रिकॉर्ड बिक्री

नई दिल्ली। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मंगलवार को कहा कि खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक के सर्वोच्च स्तर 1,87,105 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अयोग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में यह बिक्री 1,70,551.37 करोड़ रुपए रही थी, जबकि 2013-14 में यह 31,154 करोड़ रुपए थी। चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 2.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन 2013-14 में 26,109 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में करीब पांच गुना होकर 1,25,296 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर, खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों में कुल रोजगार 2013-14 में 1.30 करोड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर 2.04 करोड़ हो गया।

बीएसएनएल की जोरदार कमबैक, रेटेन्यू में बड़ी छलांग

नईदिल्ली। देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) एक बार फिर चर्चा में है। कुछ साल पहले तक भारी कर्ज और लगातार घाटे के चलते यह कंपनी बंद होने की कगार पर मानी जा रही थी लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार के सुधारों और नेटवर्क अपग्रेड के बाद बीएसएनएल की सालाना कमाई बढ़कर करीब 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिससे यह टेलीकॉम सेक्टर में फिर से मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरी है। दूरसंचार राज्यमंत्री के अनुसार, कंपनी का राजस्व दो साल में करीब 21,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 19% की ग्रोथ दर्शाता है। इसके साथ ही ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी सुधार देखने को मिला है।

घटना विदेशी मुद्रा भंडार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता संकट

सनत जैन

पिछले दस वर्षों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय शेयर बाजार में भारी निवेश किया, यह निवेश दीर्घकालिक औद्योगिक विकास की बजाय अल्पकालिक मुनाफाखोरी पर आधारित रहा। जब-जब वैश्विक परिस्थितियाँ अनुकूल रही, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से बड़ा लाभ कमाया। भारतीय शेयर बाजार का उपयोग सट्टा बाजार के रूप में करके विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से भारी कमाई की है। शेयर बाजार में संकट आते ही भारी निकासी शुरू कर दी। पिछले दो वर्षों में ही लगभग 78 बिलियन डॉलर की निकासी यह साबित करती है, विदेशी निवेशक पूंजी भारत को स्थायी विकास में साझेदार नहीं, बल्कि लाभ कमाने का बाजार मानकर कमाई कर भारतीय पूंजी को विदेश तो जा रही थी। इसके विपरीत भारतीय संस्थागत निवेशकों—

बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड—ने बाजार को संभालने के लिए लगातार शेयर बाजार में निवेश किया। इसका अर्थ यह है कि शेयर बाजार की वास्तविक मजबूती घरेलू निवेश पर टिकी हुई है। जबकि विदेशी निवेशकों ने निवेश निकालकर अस्थिरता को बढ़ाने का काम किया है।

स्थिति की गंभीरता केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। भारत का आयात, लगातार निर्यात से अधिक कई वर्षों से बना हुआ है। कच्चे तेल, गैस और उर्वरक जैसे आवश्यक उत्पादों के लिए भारत को भारी मात्रा में डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तनाव, विशेषकर पश्चिम एशिया के संकट और अमेरिका-ईरान टकराव ने ऊर्जा कीमतों को बढ़ाया है। दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। यदि रुपया 100 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंचता है, तो आयातित महंगाई और भी



भयावह हो जाएगी।

चिंता का सबसे बड़ा विषय विदेशी मुद्रा भंडार है। जिस विदेशी मुद्रा भंडार को सरकार आर्थिक सुरक्षा कवच बताती रही है। उसकी वास्तविक स्थिति अब भारी दबाव में दिखाई दे रही है। रिजर्व बैंक रुपए को संभालने के लिए बाजार में डॉलर बेच रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति जारी रही, तो भारत को भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ सकता है। 1991 के आर्थिक संकट की यादें फिर ताजा होने लगी हैं। उस समय भी आयात भुगतान और विदेशी मुद्रा की कमी सबसे

बड़ी समस्या बनी थी।

एक अन्य गंभीर पहलू भारतीय पूंजी का विदेशों की ओर पलायन है। पिछले वर्षों में अनेक उद्योगपतियों और अरबपतियों ने विदेशों में निवेश बढ़ाया है। लाखों भारतीय नागरिकों ने विदेशी नागरिकता तक ली है। इससे यह संकेत मिलता है, देश का बड़ा पूंजी वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर स्वयं आश्वस्त नहीं है। ऐसे समय में जब देश के भीतर निवेश और रोजगार सृजन की आवश्यकता है, तब बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा अमेरिका एवं अन्य देशों में अरबों डॉलर का निवेश करना भारतीय अव्यवस्था को लेकर कई प्रश्न खड़े करता है।

सरकार की गलत आर्थिक नीति आलोचना के घेरे में आ गई है। केंद्र और राज्य सरकारों पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा नियंत्रण से बाहर जाता

दिखाई दे रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से लगातार भारी लाभांश लेना और बैंकों पर निर्भरता बढ़ाना, यह दर्शाता है, सरकार के पास संसाधनों का संकट गहराता जा रहा है। यह आशंका व्यक्त की जाने लगी है भारत लेहमन ब्रदर्स जैसी स्थिति में पहुंच सकता है। भारतीय वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के आर्थिक संकेतकों में बढ़ती अस्थिरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी विशाल घरेलू बाजार, सेवा क्षेत्र और कृषि उत्पादन पर टिकी हुई है। यदि आयात पर नियंत्रण, पूंजी पलायन, बढ़ता कर्ज और कमजोर होती मुद्रा पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो आर्थिक मंदी और महंगाई का दोहरा संकट भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा सकता है। सरकार को उत्पादन, निर्यात, रोजगार और घरेलू निवेश को मजबूत करने वाली ठोस आर्थिक नीतियों पर काम करना होगा।

तेंदूपत्ता खरीदी की दर बढ़ाने का सकारात्मक असर अब वनांचल में दिखाई दे रहा

वनवासियों में जगा सरकार के प्रति अटूट विश्वास’

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा तेंदूपत्ता खरीदी की दर बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा किए जाने का सकारात्मक असर अब वनांचल क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। शासन के इस ऐतिहासिक फैसले ने हजारों तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और खुशहाली जगाई है। मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम बहेराटोला निवासी तेंदूपत्ता संग्राहक अमोल सिंह भी उन लोगों में शामिल हैं, जिनकी जिंदगी इस निर्णय से बदली है। उनके चेहरे पर आज की खुशी और आत्मविश्वास इस नीति की सफलता की कहानी खुद बयां करता है।

‘बढ़ी दर से मिली मजबूत आर्थिक सुरक्षा’

तेंदूपत्ता संग्राहक अमोल सिंह बताते हैं कि तेंदूपत्ता संग्रहण ही हमारे परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है। पहले कड़े श्रम और मेहनत के मुकाबले आय बहुत कम मिलती थी, जिससे परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती थी। अब राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने से हमें हमारे पसीने का सही मूल्य मिल रहा है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हुई है।

बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर बढ़ा ध्यान’

अमोल सिंह ने साझा किया कि बढ़ी हुई आय ने उनके परिवार की प्राथमिकताएं बदल दी हैं। अब वे अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई और उज्ज्वल भविष्य के लिए



धन संचय कर पा रहे हैं। परिवार के स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी जरूरतों पर अब वे पहले से बेहतर खर्च करने में सक्षम हैं। वनांचल में रहने वाले परिवारों के लिए यह निर्णय केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि समाज में सम्मान और सुरक्षा का सुखद एहसास लेकर आया है।

वनवासियों में जगा सरकार के प्रति अटूट विश्वास’

अमोल सिंह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री श्री केदार कश्यप के प्रति सहृदय आभार जताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार वनवासियों, आदिवासियों और श्रमिकों के हित में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ अब दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के अंतिम छोर तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव दिखाई दे रहे हैं।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

अमोल सिंह का मानना है कि सरकार के इस कदम से वनांचल के परिवारों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिली है, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार ऐसे ही जनहितकारी निर्णय लेती रहेगी, जिससे वनवासियों को सम्मानजनक जीवन जीने के नए अवसर मिलते रहें। यह सफलता की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि सरकार की संवेदनशील नीतियां जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं, तो वे केवल उनकी आय नहीं बढ़ातीं, बल्कि उनके भीतर व्यवस्था के प्रति विश्वास, सम्मान और नए सपनों को भी जन्म देती हैं।

काम में बेवजह देरी करने वाली एजेंसियों पर होगी सख्त कार्रवाई: मुख्य सचिव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में ई-प्रगति पोर्टल में दर्ज राज्य की अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाए और आ रही बाधाओं को तत्काल दूर कर नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में बेवजह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक में विशेष रूप से पोर्टल पर दर्ज राज्य की 5 अति-महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। वर्किंग वुमेन हॉस्टल, उसलापुर (बिलासपुर), वर्किंग वुमेन



हॉस्टल, कोनी (बिलासपुर), 4^थ स्टेशन क्रेड्ड मोबाइल टॉवर स्थापना (बिलासपुर), मोबाइल टॉवर हेतु विद्युत अधोसंरचना परियोजना (बिलासपुर) और सिकारसर कोडार रिसीवर लिंक केनाल (गरियाबंद जिला)।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक परियोजना की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट ई-पोर्टल पर फोटो जियोटैग के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करें, ताकि कार्यों की वास्तविक स्थिति की पारदर्शी मॉनिटरिंग हो सके। उन्होंने जिलों

में मोबाइल टॉवर स्थापना के मार्ग में आ रही भूमि आवंटन या अन्य तकनीकी दिक्कतों को संबंधित कलेक्टरों से समन्वय कर शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए।

इस समीक्षा बैठक में मंत्रालय से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन विभाग तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 21 जिलों के कलेक्टर शामिल हुए, जिनमें बीजापुर, कांकेर, कोरबा, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, नारायणपुर, रायगढ़, सुकमा, बलौराबाजार-भाटापारा, बलरामपुर, धमतरी, गरियाबंद, जशपुर, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, दंतेवाड़ा एवं कोण्डागांव शामिल हैं।

नीतू कमल और डी श्रवण केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी में आईजी के लिए इपैनल



■ छत्तीसगढ़ कैडर के दो आईपीएस अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी नीतू कमल और डी श्रवण को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी में आईजी के लिए इपैनल किया गया है।

आईपीएस नीतू कमल वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, जबकि डी

श्रवण राष्ट्रीय जांच एजेंसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोनों अधिकारियों की कार्यशैली और अनुभव को देखते हुए केंद्र ने उन्हें अहम जिम्मेदारियों के लिए चयनित किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में देशभर के वर्ष 2001 से 2008 बैच तक के कुल 67 आईपीएस अधिकारियों को आईजी और डीआईजी स्तर के पदों के लिए इपैनल किया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के इन दोनों अधिकारियों के इपैनल होने को राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

महंत के बयान पर मुख्यमंत्री साय का तंज

संतों का आशीर्वाद तो सभी को मिलता है



रायपुर। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत की ओर से बाबाओं पर दिए बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है सारे संत का आशीर्वाद तो सभी को मिलता है। उनके पास तो सभी जाते हैं, यह उनका अनुभव होगा।

दरअसल, चरणदास महंत ने सोमवार को मनेन्द्रगढ़ दौरे में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा

कि रामभद्राचार्य जिस प्रकार से भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वह सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं। ऐसे बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से उठा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जैसे सभी बाबा फर्जी हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाने की अपील की. साथ ही कहा कि हम तो कण कण में भगवान मानने वाले लोग हैं। हमारे तो कण-कण में भगवान हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर

थे। आज वहां से लौटने के बाद उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर कहा कि उन्होंने सबके साथ, विश्वास, प्रयास और विकास के साथ काम किया है।सीएम साय ने बताया कि दिल्ली में जनजाति संस्कृति का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात हुई और उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्यौता दिया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी मुलाकात की है।

वहीं डीलिट्रिंग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनजाति समाज बहुत पहले से मांग करते आ रहा है। धर्मोत्तरित होने के बाद अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अपना रीति रिवाज छोड़कर दूसरे धर्म में लोग चले जाते हैं ऐसे लोग एसटी और अल्पसंख्यक दोनों का दोहरा लाभ लेते हैं।

अपनी डगमगाती कुर्सी बचाने के लिए महंत ने दिया अभद्र बयान : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दिए गए अमर्यादित और अभद्र वक्तव्य की कड़े शब्दों में तीखी निन्दा की है। श्री सोनी ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता के दिलों में रची-बसी सनातन संस्कृति और पूज्य संत समाज का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल हो चुका है।

?भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और रामसेतु को नकारने का दुस्साहस



किया। यह वही कांग्रेस है जिसने देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भव्य राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का आमंत्रण तक ठुकरा दिया। सनातन संस्कृति और जन-आस्था पर लगातार चोट पहुंचाने वाली कांग्रेस अब खुलेआम हमारे पूज्य संतों के अपमान पर उतारू हो गई है। ?श्री सोनी ने चरणदास महंत के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस के भीतर अपनी ही कुर्सी पर मंडराते खरटे और राजनीतिक वजूद को बचाने

की छटपटाहट साफ दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस पार्टी में पद पाने या अपनी हैसियत बचाए रखने के लिए ‘सनातन विरोधी बयान देना’ एक अनिवार्य शर्त बन चुकी है। शरीं तेलें अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने और आलाकमान को खुश करने के लिए ही देश के शीर्ष संतों के खिलाफ महंत ने इस तरह की घटिया और ओछी बयानबाजी की है। श्री सोनी ने कहा कि संतों के प्रति ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना पूरी राज्य की संस्कृति को कलंकित करने जैसा है। छत्तीसगढ़ की धर्मप्राण जनता अपने पूज्य संतों का यह चोर अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। महंत को अपने इस अमर्यादित वक्तव्य के लिए तत्काल पूरे देश और संत समाज से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

भाजपा अवसरवादी राजनीति कर रही : दीपक बैज

रायपुर। डी-लिस्टिंग मामले में भाजपा अवसरवादी राजनीति कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। संसद में कानून बनाने का अधिकार इस सरकार के पास है, विधानसभा में कानून बनाने का अधिकार इनके पास है तो डी-लिस्टिंग मामले में कानून बनाने से क्यों डर रहे है? भाजपा आदिवासी नेताओं को बुलाकर भाषण देकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। डी-लिस्टिंग के मामले में आदिवासी समाज के पीड़ा से भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। आदिवासियों के हितों की भाजपा को कोई चिंता नहीं है। यह जैसे धर्मांतरण के मामले में राजनीति करती है, वैसे ही डी-लिस्टिंग के मामले में राजनीति कर रहे है। इनको कानून बनाने से किसने रोका है? भाजपा को लगता है कि डी-लिस्टिंग होना चाहिये, जो कानून बनाये, केवल गुमराह करने का काम नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों के हित और अधिकार से कोई सरकार नहीं है, वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून का सर्वाधिक उल्लंघन भाजपा शासित राज्यों में ही किया जा रहा है। अपने पूंजीपति मित्रों के आर्थिक लाभ और अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए भाजपा केवल वर्ग संघर्ष कराना चाहती है।



विधायक से ठगी राज्य में कोई सुरक्षित नहीं : शुक्ला

रायपुर। भाजपा विधायक पुरेंद्र मिश्रा के साथ सायबर ठगी इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार का खौफ अपराधियों में खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। कुछ दिन पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता धरमलाल कौशिक का संरेआम मोबाईल लूट लिया जाता है। भाजपा के विधायक के साथ ठगी हो जाती है और ठगी ऐसे विधायक के साथ हो जाती है जो पेशे से अधिवक्ता है। इस घटना से अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद है कि ऑफलाइन,



ऑनलाईन ठगी हो रही है। लूट, हत्या, चाकुबाजी की घटना अब आम हो गया है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब भाजपा के दो विधायक के साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं हो सकता। पुरेंद्र मिश्रा पढ़े लिखे विधायक है वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीए के नाम पर ठगी के शिकार कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पीए को पहले भी पैसा देते रहे है तभी उन्होंने उसकी मांग पर बिना शंका किये तत्काल ऑनलाइन पैसे भेज दिया।

सफाई व्यवस्था ध्वस्त रायपुर बना कचरापुर: ठाकुर

रायपुर। रायपुर में साफ सफाई नहीं होने के लिए ट्रिपल इंजन सरकार को दोषी ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा ट्रिपल इंजन सरकार में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई रायपुर अब कचरापुर लगने लगी है। राजधानी के चौक चौराहों गली मोहल्लों में कचरा का ढेर लग गया है नाली बजबजा रही है गंदगी और दुर्गंध, मच्छर से लोग हलाकान है। गर्मी में गंदगी इतनी बढ़ गई तो कल्पना कीजिये बारिश में राजधानी



में गंदगी का क्या हाल होगा। अभी एक घण्टे की बारिश में नाली के कचरे सड़कों पर आ जा रहे है घरों में गन्दा पानी घुस जा रहा है तो बारिश जब निरन्तर होगी तो शहर में गंदगी की बाढ़ आ जायेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार पर सब कुछ बेहतर होना एवं विकास की गति बढ़ने के दावा हवाई हवाई साबित हुई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा रायपुर का ये बुरा हाल के लिए महापौर मोनल चौबे जिम्मेदार है उनके नियंत्रण में निगम प्रशासन नहीं है न ही महापौर की निगम में सुनी जाती है कई बार निगम के फैसले का विरोध जनता ने किया तो महापौर का बयान आया है ये उनकी जानकारी में नहीं है।ये परिस्थितियां नगरीय प्रशासन मंत्री और पश्चिम विधायक राजेश मृण्त के बीच मतभेद के कारण हुई है।

खाद की लिमिट घटाना किसानों के साथ अन्याय : वर्मा

रायपुर। किसानों को प्रति एकड़ दिये जाने वाले खाद की लिमिट में की गई कटौती को सरकार का किसान विरोधी निर्णय बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि इस बार किसानों को पिछले खरीफ सीजन में वितरित डीएपी का मात्र 60 प्रतिशत और यूरिया का 80 प्रतिशत देने का तुगलकी फरमान जारी किया गया है, केवल यही नहीं भाजपा सरकार ने सोसायटियों से नकदी और



खाद के ऋण का रैसियो ही बदल कर खाद की लिमिट में 10 प्रतिशत की कटौती कर दिया है, नई व्यवस्था के अनुसार, कृषि ऋण में अब 70 प्रतिशत नकद राशि और केवल 30 प्रतिशत वस्तु (खाद-बीज) के रूप में दी जा रही है। पूर्व में, किसानों को ऋण का 60 प्रतिशत नगदी और 40 प्रतिशत खाद, बीज के रूप में मिलते थे।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि खेती का समय निकल रहा है, किसान परेशान है, लेकिन सिस्टम और सरकार गलत बयान कर रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम दावा कर रहे कि प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक है, दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने में 50 प्रतिशत उर्वरकों की कमी बता रहे।

जर्किन और डब्बों में पेट्रोल-डीजल दिया जाये: देवलाल

रायपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने छत्तीसगढ़ में जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश कि सिर्फ किसानों को हीजर्किन और डब्बों में पेट्रोल डीजल दिया जायेगा, यह बेटुका आदेश है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि पेट्रोल पंपों से जर्किन, डब्बों अथवा अन्य पात्रों में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाना आम उपभोक्ताओं की वास्तविक समस्याओं से दूर एक



अव्यावहारिक और जनविरोधी निर्णय बताया है। आज शहरों और कालोनियों में बड़ी संख्या में डीजी सेट (डीजल जनरेटर) उपयोग में लाए जाते हैं, जिनके लिए डीजल की आवश्यकता पड़ती है। लाइट बंद होने पर छत सेट के जरिये ही सभी बहु मंजिला ईमारतों में लिफ्ट भी चलती है,लिफ्ट बंद होने पर यदि कोई लिफ्ट में फंस्ता है और उसकी जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन? कलेक्टर, जिला प्रशासन या सरकारवैसे भी डीजी सेट को डीजल पंप तक ले जाना संभव नहीं है। केटरिंग वाले भी डीजल भट्टी का उपयोग करते हैं और ढाबों में भी डीजल भट्टी उपयोग होती है। गैस सिलिंडर की कमी और डीजल भी ना मिलने पर कहीं ना कहीं खाने की चीजों के दाम बढ़ेंगे।

राज्य सहकारी विकास समिति की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न

किसानों को बनाया जाए आत्मनिर्भर: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य की सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक खाद, बीज, दवा, बैंकिंग और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं सुलभता से पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के कृषकों को सशक्त बनाने के लिए सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही प्राथमिक कृषि साख समितियों को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्हें दुग्ध, मत्स्य पालन और लघु



वनोंपज के कार्यों से सीधे जोड़ा जाए।

मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में समितियों के गठन, उद्देश्यों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत पैक्स (चैंबे) गोदामों के निर्माण की प्रगति की गहन समीक्षा की

गई। समितियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी आवश्यक सुविधाएं ग्रामीण अंचलों में विस्तारित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में राज्य की सभी पैक्स समितियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी

निर्यात समिति और राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति की अनिवार्य सदस्यता दिलाने की रणनीति पर चर्चा की गई।समर्थन मूल्य पर मक्का और दलहन के सुचारु उपार्जन हेतु पैक्स समितियों एवं किसानों का पंजीयन छब्थ्य और छ।ष्यर्क के आधिकारिक पोर्टल्स पर करने के निर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए पैक्स, दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम (डपबतव ङ्ड) स्थापित करने तथा सभी सदस्यों को रूपे (बचल) , किसान क्रेडिट कार्ड (ज़ब्ब) उपलब्ध कराने के कार्यों की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों में मल्टीफ्रीड इथेनॉल संयंत्रों के निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिए तत्काल समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, राज्य के शहरी सहकारी बैंकों को अम्ब्रेला संगठन से जोड़ने, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने, पैक्स कंप्यूटरीकरण, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना, समितियों के लिए श्रैंकिंग फ़ेमवर्कश तैयार करने तथा पैक्स के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया।



रायपुर। प्रदेश के वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री ी लखन लाल देवांगन ने आज नवा रायपुर स्थित जीएसटी भवन स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में विभागीय आयुक्तों की विस्तृत समीक्षा की और आगामी महीनों के लिए जिलेवार विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आबकारी मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस रणनीति अपनाने, दुकानवार समीक्षा करने और

अनुशासन के साथ कार्य संपादन के निर्देश दिए। बैठक में वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, आबकारी आयुक्त पडुम सिंह एल्मा, विशेष सचिव आबकारी श्री देवेन्द्र भारद्वाज, आबकारी मुख्यालय, बेवरेजेस कारपोरेशन के अधिकारियों सहित जिले से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित थे। आबकारी मंत्री देवांगन ने राज्य की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों को

अन्य राज्यों की मदिरा के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने और सीसीटीवी कैमरों के सुचारू संचालन की निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि मदिरा के अवैध परिवहन एवं बिक्री पर कोचियों के विरुद्ध प्रभावी कार्य करें। सभी जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करें आबकारी उपनिरीक्षक एवं नीचे का अमला अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध समझौता न करें। इसके अलावा विभाग में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार मदिरा स्कंध का संधारण सुनिश्चित करें।